सांध्य दैनिक

नई दृष्टिबिंदु

सच की शक्ति, जनता की दृष्टि

PRGI Reg No - CTHIN/25/A3746

सु-विचार

"जिन्दगी में हर मोड़ हमारी मर्जी का नहीं होता,
कभी वक्त रास्ता चुनता है तो कभी हालात मंजिल बदल देते हैं...!!"
अज्ञात...

वर्ष–01 अंक–138 | संपादक आलोक तिवारी | दुर्ग, रविवार 07 जून 2026 | पृष्ठ 08 | मूल्य –2 रुपए

नीट पेपर लीक पर दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन, शिक्षा मंत्री को 7 दिन का अल्टीमेटम

सोनम वांगचुक पहुंचे जंतर-मंतर, मुख्यधारा मीडिया पर कवरेज न करने का आरोप

नई दृष्टिबिंदु / नईदिल्ली

नीट पेपर लीक मामले को लेकर युवाओं का आक्रोश शुक्रवार को दिल्ली के जंतर-मंतर पर दिखा। कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के बैनर तले हुए इस प्रदर्शन में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा और पंजाब समेत कई राज्यों से हजारों छात्र, महिलाएं और बुजुर्ग शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के तत्काल इस्तीफे की मांग की।

सोनम वांगचुक ने दिया समर्थन

दोपहर में शिक्षाविद और पर्यावरणविद् सोनम वांगचुक के जंतर-मंतर पहुंचने पर आंदोलन में जोश बढ़ गया। वांगचुक ने छात्रों के साथ मंच साझा किया और उनकी मांगों का समर्थन किया।

7 दिन का अल्टीमेटम

सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास, विजय दहिया और आशुतोष रांका ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्र सरकार को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि यदि 7 दिनों के भीतर शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं देते हैं तो

आंदोलन देशव्यापी किया जाएगा और हर राज्य का युवा सड़कों पर उतरेगा।

मीडिया कवरेज पर उठाए सवाल

आंदोलनकारियों ने आरोप लगाया कि बड़े टीवी चैनलों और राष्ट्रीय न्यूज एजेंसियों ने प्रदर्शन को कवरेज नहीं दी। जंतर-मंतर पर भीड़ ने कुछ चैनलों के खिलाफ गोदी मीडिया के नारे लगाए। इसके बाद कुछ रिपोटर्रों को बिना लोगो के माइक इस्तेमाल करते देखा गया। हालांकि सोशल मीडिया पर दिनभर यह मुद्दा ट्रेंड करता रहा। पुलिस के दखल के बाद शाम को प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से समाप्त हुआ। छात्रों ने कहा कि यह सिर्फ शुरुआत है।

आज से घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर 29 रुपये महंगा

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर-नईदिल्ली

घरेलू रसोई गैस एलपीजी फिर महंगी हो गई है। एलपीजी की कीमत में प्रति सिलेंडर 29 रुपये की बढ़ोतरी की गई है जो कि सात जून से लागू होगी। तीन महीनों में यह दूसरी बढ़ोतरी है। इसके पीछे ईरान संकट है। बताया गया है कि सरकारी फ्यूल रिटेलर्स को ग्लोबल एनर्जी की बढ़ती कीमतों से जूझना पड़ रहा है।

सूत्रों से पता चला है कि 7 जून से दिल्ली में 14.2 किलोग्राम वाले एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत 913 रुपये से बढ़कर 942 रुपये हो जाएगी। इससे पहले 7 मार्च को प्रति सिलेंडर 60 रुपये की बढ़ोतरी की गई थी, जब वेस्ट एशिया में संघर्ष के कारण ग्लोबल एनर्जी सप्लाई में रुकावट आई थी और इंटरनेशनल फ्यूल की कीमतें बढ़ गई थीं।

इंडस्ट्री के सूत्रों का तर्क है कि पिछली बढ़ोतरी से घरेलू एलपीजी बिक्री पर हुए नुकसान की केवल आंशिक भरपाई ही हो पाई थी। हालिया बदलाव से पहले, सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को बेचे जाने वाले हर एलपीजी गैस सिलेंडर पर लगभग 703 रुपये का नुकसान हो रहा था। पहली जून को ही 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हुई थी। दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर 42 रुपये महंगा होकर अब 3113.50 रुपये का हो गया है। वहीं कोलकाता में इसकी कीमत 53.50 रुपये बढ़कर 3255.50 रुपये पहुंच गई। इतना ही नहीं छोटे व्यापारियों और नागरिकों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले 5 किलोग्राम के एफटीएल सिलेंडर की कीमत में भी 11 रुपये का इजाफा किया था। दिल्ली में ये छोटा सिलेंडर अब 821.50 रुपये की नई दर पर मिलता है।

एलपीजी की कीमतों में यह बढ़ोतरी तेल की कीमतों में व्यापक बढ़ोतरी के दौर के बीच हुई है। मई से अबतक पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कुल मिलाकर 7.50 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है, जबकि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस (CNG) की दरों में लगभग 6 रुपये प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी हुई है। इंडस्ट्री के सूत्रों के मुताबिक, हालिया बढ़ोतरी के बावजूद ऑयल कंपनियां पेट्रोल और डीजल को लागत से कम कीमत पर बेच रही हैं, जिससे उन्हें पेट्रोल पर लगभग 11 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 33.6 रुपये प्रति लीटर का नुकसान हो रहा है।

फ्रेट कॉरीडोर परियोजना : 25 गांवों में जमीन की खरीदी-बिक्री पर लगी रोक

दुर्ग। कलेक्टर अभिजीत सिंह ने ईस्ट एण्ड वेस्ट डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर परियोजना के निर्माण को लेकर बड़ा आदेश जारी किया है। प्रभावित ग्रामीणों के हितों की रक्षा और परियोजना में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए जिले के 25 गांवों में निजी भूमि के खाता विभाजन, अंतरण, व्यपवर्तन और खरीदी-बिक्री को तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक अस्थायी रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है। कलेक्टर द्वारा 3 जून को जारी आदेश में संशोधन करते हुए इन गांवों की सूची जारी की गई है। संशोधित आदेश के अनुसार दुर्ग तहसील के ग्राम बिरेझर, चंगोरी, कोनारी, चंदखुरी, हनोदा, खम्हरिया, उमरपोटी, उतई, डुमरडीह शामिल हैं। वहीं पाटन तहसील के ग्राम परेवाडीह, पहंडोर, औंधी, मगरघटा, बेन्द्री, नारधी, महकाकला, महकाखुर्द, कुरूदडीह, बटंग में भी रोक लगाई गई है। भिलाई-3 तहसील के सिरसाकला, परसदा (पाहंदा), सोमनी, गनियारी, देवबलोदा और उरला गांव भी प्रतिबंधित सूची में शामिल किए गए हैं। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि पूर्व आदेश की शेष शर्तें यथावत रहेंगी। यह प्रतिबंध फ्रेट कॉरीडोर परियोजना के लिए प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया पूरी होने तक लागू रहेगा।

नागपुर में पकड़ा अंतर्राज्यीय ऑनलाइन सट्टा सिंडिकेट, 9 आरोपी हुए गिरफ्तार

डेढ़ करोड़ का लेन-देन, 23 लाख के जेवरात सहित 26 मोबाइल, 85 एटीएम कार्ड बरामद

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग

दुर्ग पुलिस ने अंतर्राज्यीय ऑनलाइन सट्टा सिंडिकेट का भंडाफोड़ करते हुए मास्टरमाइंड सहित 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थाना छावनी पुलिस की कार्रवाई में नागपुर में संचालित ऑनलाइन सट्टा सेंटर पर छापा मारकर करोड़ों के अवैध कारोबार का खुलासा हुआ।

पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि छावनी निवासी निशांत कुमार गुप्ता (29) लंबे समय से विभिन्न राज्यों में छिपकर ऑनलाइन सट्टा चला रहा है और वर्तमान में अपने घर से भी क्रिकेट बेटिंग कर रहा है। सूचना पर पुलिस ने निशांत को हिरासत में लिया। मोबाइल और डिजिटल उपकरणों की जांच में सूचना सही पाई गई।

पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह "C-B Cricket Buzz Betting App" और "RubyBet" प्लेटफॉर्म की आईडी चलाता है। पुलिस से बचने के लिए उसने नागपुर में किराये का मकान लेकर यूपी-बिहार के युवकों को 20-25 हजार मासिक वेतन पर रखा था। ये युवक डिपॉजिट, विड्रॉल, अकाउंट संचालन और आईडी प्रबंधन का काम करते थे।

नागपुर में दबिश, 8 आरोपी रंगे हाथ पकड़े

निशांत की निशानदेही पर दुर्ग पुलिस की टीम ने नागपुर स्थित मकान में दबिश दी। मौके से 8 आरोपियों को ऑनलाइन सट्टा चलाते रंगे हाथ पकड़ा गया। गिरफ्तार आरोपियों में 6 उत्तरप्रदेश के आजमगढ़, मऊ, महाराजगंज जिले के और 2 बिहार के दरभंगा जिले के हैं।

प्रतिमाह डेढ़ करोड़ का ट्रांजेक्शन

पूछताछ में खुलासा हुआ कि गिरोह प्रतिदिन 4 से 5 लाख और प्रतिमाह लगभग डेढ़ करोड़ रुपये का ऑनलाइन लेन-देन करता था। मुख्य आरोपी निशांत लगातार ठिकाने बदलकर पुलिस से बच रहा था।

फर्जी खातों से होता था लेन-देन

जांच में सामने आया कि ऑनलाइन सट्टे के पैसों के लेन-देन के लिए फर्जी और बेईमानी से हासिल किए गए बैंक खाते, एटीएम कार्ड और सिम कार्ड इस्तेमाल किए जा रहे थे। सट्टे की रकम को परत-दर-परत अलग-अलग खातों में ट्रांसफर कर स्रोत छिपाया जाता था। पुलिस ने इस मामले में बीएनएस की धारा 317(4), 318(4) और टेलीकॉम एक्ट की धारा 42 भी जोड़ी है।

23 लाख के जेवरात जप्त

ऑनलाइन सट्टे की कमाई से आरोपी निशांत ने महंगे आभूषण खरीदे थे। उसने लगभग 15 तोला सोने और डायमंड मिश्रित जेवरात महावीर ज्वेलर्स, पावर हाउस भिलाई में 10 माह पहले गिरवी रखे थे। पुलिस ने करीब 23 लाख रुपये कीमत के ये आभूषण जप्त कर लिए हैं।

ये सामान हुआ बरामद

पुलिस ने 26 एंड्रॉयड मोबाइल, 3 लैपटॉप, 2 आईपैड, 85 एटीएम कार्ड, 18 पासबुक, 45 सिम कार्ड, 19 एक्सटेंशन बोर्ड, 19 पावर बैंक, हिसाब-किताब रजिस्टर और 1,54,620 रुपये नगद बरामद किए हैं।

गिरफ्तार आरोपी में निशांत कुमार गुप्ता, 29 वर्ष, निवासी कैंप-02, भिलाई मुख्य आरोपी, आईडी संचालक, अखिलेश यादव, 22 वर्ष, आजमगढ़, उ.प्र., पंकज यादव, 22 वर्ष, आजमगढ़, उ.प्र., आशीष जायसवाल, 20 वर्ष, मऊ, उ.प्र., विशाल पटेल, 29 वर्ष, महाराजगंज, उ.प्र., शिवम चौहान, 23 वर्ष, आजमगढ़, उ.प्र., जयहिंद यादव, 22 वर्ष, आजमगढ़, उ.प्र., वेचन मुखिया, 24 वर्ष, दरभंगा, बिहार और भागीरथ राम, 35 वर्ष, दरभंगा, बिहार शामिल हैं। थाना छावनी में अपराध क्रमांक 371/2026 के तहत

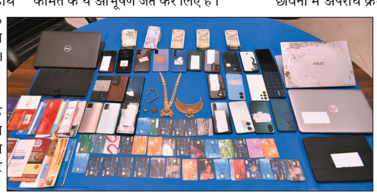

छत्तीसगढ़ जुआ (प्रतिषेध) अधिनियम की धारा 7 एवं बीएनएस की धारा 112, 61(2), 317(2), 317(3), 317(4) तथा टेलीकॉम अधिनियम की धारा 42 के तहत मामला दर्ज कर वित्तीय नेटवर्क की विस्तृत जांच की जा रही है।

मोहला-मानपुर में 75 लाख की अवैध शराब जब्त, महाराष्ट्र ले जा रहा ट्रक को पुलिस ने पकड़ा

800 पेटी शराब बरामद, मध्यप्रदेश से गड़चिरोली ले जा रहा था आरोपी

नई दृष्टिबिंदु / मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी

जिले की पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए मध्यप्रदेश से महाराष्ट्र ले जाई जा रही लगभग 800 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब जब्त की है। ट्रक सहित जब्त सामग्री की कुल कीमत 75 लाख 28 हजार रुपये आंकी गई है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाय. पी. सिंह के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के तहत शुक्रवार को थाना मानपुर पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि अंबिकापुर पासिंग का सफेद रंग का ट्रक उऋ15 ऊे4515 में भारी मात्रा में अवैध शराब लोड कर मोहला, मानपुर व औंधी मार्ग से महाराष्ट्र बॉर्डर ले जाई जा रही है।

सूचना पर एसडीएम कार्यालय मानपुर के पास एमसीपी प्वाइंट लगाकर जांच शुरू की गई। इस दौरान ट्रक आता दिखा। पुलिस को देख चालक भागने लगा, जिसे घेराबंदी कर पकड़ लिया गया। आरोपी की पहचान बलराम सिंह डांगी, निवासी नागपुर (महाराष्ट्र) के रूप में हुई।

पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है। तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की जांच जारी है। यह कार्रवाई थाना प्रभारी मानपुर निरीक्षक कपिल देव चंद्रा के नेतृत्व में थाना स्टाफ व साइबर सेल मोहला की टीम ने की।

50 लाख की शराब, 25 लाख का ट्रक जब्त

ट्रक की तलाशी में 100 पेटी रॉयल स्टेज पौवा 4800 नग कीमत 9.60 लाख, 300 पेटी बीयर 7200 नग कीमत 13.68 लाख और 400 पेटी गोवा व्हिस्की पौवा 20,000 नग कीमत 27 लाख रुपये की बरामद हुई। कुल 50.28 लाख की शराब और 25 लाख का ट्रक जब्त किया गया।

गड़चिरोली में खपाने की थी तैयारी

पूछताछ में आरोपी ने बताया कि शराब मध्यप्रदेश के बैतूल जिले के मुलताई से लोड की गई थी। इसे नागपुर, देवरी, चिचोला, राजनांदगांव, अंबागढ़ चौकी, मोहला, मानपुर होते हुए महाराष्ट्र बॉर्डर ले जाना था। गडचिरोली में शराब दुकान नहीं होने से बॉर्डर के गांवों में खपाने की योजना थी। आरोपी महाराष्ट्र के शैलेश नामक व्यक्ति के संपर्क में था।

भिलाई में यूपीआई फ्रॉड : खाते से उड़ाए 2.61 लाख रुपए

नई दृष्टिबिंदु / भिलाई

भिलाई में साइबर ठगी का एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां अज्ञात साइबर अपराधियों ने एक व्यक्ति के बैंक खाते से फर्जी यूपीआई ट्रांजेक्शन के जरिए 2 लाख 61 हजार 825 रुपये निकाल लिए। पीड़ित को इस धोखाधड़ी की जानकारी तब हुई जब उसने एक होटल में मामूली भुगतान करने के बाद अपने खाते का बैलेंस चेक किया। मामले की शिकायत मिलने पर पुलिस ने अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार, बैकुंठ नगर कैंप-2 निवासी राजेश विश्वकर्मा (46) ने छावनी थाना में शिकायत दर्ज कराई है।

अलग-अलग खातों में बड़ी रकम ट्रांसफर

उन्होंने बताया कि उनके बैंक ऑफ बड़ौदा खाते से 14 मई से 18 मई के बीच अज्ञात व्यक्ति द्वारा यूपीआई माध्यम से कई लेनदेन किए गए। इन ट्रांजेक्शनों के जरिए अलग-अलग खातों में बड़ी रकम ट्रांसफर कर दी गई। पीड़ित ने पुलिस को बताया कि 18 मई की शाम वह पावर हाउस स्थित एक होटल में गए थे। वहां उन्होंने यूपीआई के जरिए 60 रुपये का भुगतान किया। भुगतान के बाद जब उन्होंने अपने बैंक खाते का बैलेंस देखा तो खाते में अपेक्षा

से काफी कम राशि दिखाई दी।

इसी दौरान उनके मोबाइल फोन पर खाते से 70 हजार रुपये कटने का संदेश भी प्राप्त हुआ। लगातार खाते से रकम निकलने के मैसेज मिलने के बाद राजेश विश्वकर्मा ने अपने बैंक खाते की पूरी जांच की। जांच में पता चला कि उनके खाते से कुल 2 लाख 61 हजार 825 रुपये विभिन्न ट्रांजेक्शनों के माध्यम से निकाल लिए गए हैं। उन्होंने दावा किया कि इन लेनदेन की उन्हें कोई जानकारी नहीं थी और न ही उन्होंने किसी को इसकी अनुमति दी थी। मामले का खुलासा होने के बाद उन्होंने तुरंत पुलिस से संपर्क किया।

लिखित शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की। शिकायत के आधार पर पुलिस ने प्रारंभिक जांच की और इसे साइबर धोखाधड़ी का मामला मानते हुए अज्ञात आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 318(4) के तहत अपराध दर्ज किया। पुलिस अब उन बैंक खातों, यूपीआई आईडी और मोबाइल नंबरों की जांच कर रही है, जिनमें यह राशि ट्रांसफर की गई है।

नए-नए तरीकों से लोगों को बना रहे निशाना

साइबर सेल की टीम भी मामले की तकनीकी जांच में जुटी हुई है। डिजिटल ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड, बैंकिंग डाटा और अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि साइबर अपराधी नए-नए तरीकों से लोगों को निशाना बना रहे हैं।

ऐसे मामलों में बैंक खाते और यूपीआई से जुड़ी जानकारी को सुरक्षित रखना बेहद जरूरी है। जांच के दौरान यह भी पता लगाया जा रहा है कि आरोपियों ने खाते तक पहुंच कैसे बनाई और किस माध्यम से ट्रांजेक्शन किए गए। फिलहाल पुलिस मामले की विस्तृत जांच कर रही है और संबंधित बैंकिंग संस्थाओं से भी जानकारी जुटाई जा रही है। अधिकारियों को उम्मीद है कि तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान कर जल्द कार्रवाई की जा सकेगी।

रायपुर में गैस एजेंसी मैनेजर से 10 लाख की लूट, शहर में अलर्ट

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

कमिश्नर सिस्टम लागू होने के बाद 4 महीने में सबसे बड़ी वारदात

रायपुर। राजधानी के डंगनिया इलाके में शनिवार रात अज्ञात लुटेरों ने गैस एजेंसी के मैनेजर से 10 लाख रुपए लूट लिए। घटना के बाद पूरे शहर में अलर्ट जारी कर दिया गया है।

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक टाटीबंध गैस एजेंसी के मैनेजर श्रवण साहू शाम को कलेक्शन के पैसे लेकर जा रहे थे। इसी दौरान डंगनिया इलाके में अज्ञात बदमाशों ने उन्हें रोककर 10 लाख रुपए लूट लिए। वारदात के बाद मैनेजर ने स्वयं फोन कर डीडी नगर पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। डीडी नगर पुलिस ने तत्काल नाकेबंदी कर जांच शुरू की और पूरे शहर को अलर्ट जारी किया। आरोपियों की तलाश में अलग-अलग टीमें रवाना की गई हैं। बताया जा रहा है कि राजधानी में कमिश्नर सिस्टम लागू होने के बाद पिछले 4 महीने में यह सबसे बड़ी लूट की घटना है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। फिलहाल अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

जिले में कचरा प्रबंधन को लेकर अभियान की शुरूआत, खुले में कचरा फेंकना और जलाना होगा पूर्ण प्रतिबंधित

सार्वजनिक स्थलों या जल स्रोतों पर कचरा फेंकने वालों पर कड़ी कार्रवाई , बिना स्थानीय निकाय की पूर्व अनुमति के 100 से अधिक व्यक्तियों का कोई भी आयोजन नहीं किया जा सकेगा

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग

कलेक्टर अभिजीत सिंह के मार्गदर्शन में जिले को स्वच्छ बनाने के उद्देश्य से स्वच्छता अभियान की शुरुआत की गई है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील में पारित कड़े आदेशों और विगत 5 मई 2026 को जारी गाइडलाइंस के परिपालन में जिले के ग्रामीण इलाकों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 को पूरी कड़ाई से लागू करने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत अब जिले में खुले में कचरा फेंकने, डंप करने, उसे जलाने या दबाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है।

नियमों की चौबीसों घंटे सख्त निगरानी करने और पर्यावरणीय मानकों को बनाए रखने के लिए जिला स्तर पर एक विशेष टास्क फोर्स (समिति) का भी गठन किया गया है, जो कचरा प्रबंधन से जुड़े हर मोर्चे पर पैनी नजर रखेगी। आज कलेक्टोरेट सभा कक्ष में कलेक्टर अभिजीत सिंह के अध्यक्षता में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) जिला प्रबंधन समिति की बैठक आयोजित की गई। उन्होंने इस अभियान के तहत काययीजना की समीक्षा की। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी बजरंग कुमार दुबे ने बताया कि विगत दिवस अभियान अंतर्गत एक दिवसीय हाई-टेक प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया।

इस कार्यशाला में जनपद पंचायत दुर्ग, धमधा एवं पाटन की समस्त 300 ग्राम पंचायतों के सरपंचों, सचिवों समेत राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (बिहान) व स्वच्छ भारत मिशन के 300 से अधिक मैदानी अधिकारियों और कमर्चारियों (बीपीएम, एरिया कोऑर्डिनेटर, पीआरपी, एफएल सीआरपी, कृषि, पशु व पोषण सखियों) को विशेष प्रशिक्षण दिया गया। इससे पूर्व विकासखण्ड स्तर पर भी जनप्रतिनिधियों को इस अधिनियम के तहत प्रशिक्षित किया जा चुका है।

सीईओ श्री दुबे ने अवगत कराया कि नए नियमों के मुताबिक, जिले की तस्वीर बदलने के लिए 5 बड़े मोर्चों पर कड़ाई से काम किया जाएगा, जिसमें स्रोत से ही कचरे का पृथक्कीकरण, शत-प्रतिशत डोर-टू-डोर कलेक्शन, वैज्ञानिक डिस्पोजल, पुराने डंपिंग यार्डों (लिगेसी वेस्ट) का खात्मा और स्वच्छता को जन-आंदोलन बनाना शामिल है। आम नागरिकों के लिए अब अपने घरों से निकलने वाले कचरे को 4 श्रेणियों (गीला, सूखा, सेनेटरी वेस्ट और स्पेशल केयर वेस्ट) में बांटकर देना अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही, सार्वजनिक स्थलों या जल स्रोतों पर कचरा फेंकने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, अब बिना स्थानीय निकाय की पूर्व अनुमति के 100 से अधिक व्यक्तियों का कोई भी आयोजन नहीं किया जा सकेगा, और बड़े पैमाने पर कचरा पैदा करने वाले संस्थानों (बल्क वेस्ट जनरेटर्स) को ऑनलाइन पोर्टल पर अनिवार्य पंजीकरण कराकर अपने गीले कचरे के निपटान के लिए स्वयं कंपोस्टिंग या बायोमीथनेशन प्लांट लगाने होंगे। सीईओ श्री दुबे ने पावर पाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 के मुख्य बिन्दु, महत्वपूर्ण कार्य, किन पर लागू होंगे, जिला कलेक्टर की भूमिका, जिला पंचायत की भूमिका, जनपद पंचायत एवं ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी, मुख्य दायित्व, ग्राम पंचायत की भूमिका, बल्क वेस्ट जनरेटर्स, अपशिष्ट उत्पादक की जिम्मेदारी, लक्ष्य एवं समय-सीमा, गतिविधि तथा जिला द्वारा की गई कार्यवाही पर विस्तारपूर्वक प्रकाश डाला। बैठक में एडीएम वीरेन्द्र सिंह, शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज कल्याण सहित सभी जनपद सीईओ एवं विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

खास खबर

महापौर परिषद की बैठक :रिसाली के नागरिकों को राहत, नहीं बढ़ा टैक्स, एमआईसी ने शिक्षा उपकर से राहत दिलाने शासन को लिखा पत्र

नई दृष्टिबिंदु / रिसाली-भिलाई

रिसाली निगम महापौर शशि सिन्हा और उनके सद्स्यों ने नागरिकों को राहत दी है। शुक्रवार दोपहर को हुई महापौर परिषद के बैठक में नागरिकों से लिए जाने वाले टैक्स को पिछले साल की तरह यथावत रखा है। किसी प्रकार की बढ़ोतरी नही की गई है। वहीं परिषद के सद्स्यों ने शासन को पत्र लिखने का निर्णय लिया है। जिसमें शिक्षा उपकर की राशि को हटाने की मांग रखेंगे।

महापौर शशि सिन्हा की अध्यक्षता में हुई बैठक में निर्णय लिया गया कि वर्ष 2026-27 में सम्पत्ती कर व अन्य कर का स्लैब यथावत रहेगा। एमआईसी मेंमबरों का कहना था कि उनके निर्णय से आम नागरिकों को राहत मिलेगी। वहीं दूसरी ओर निगम क्षेत्र में स्वयं का स्कूल नहीं होने पर शिक्षा उपकर की राशि को नहीं लिए जाने के लिए शासन को शहर सरकार पत्र लिखेगी। महापौर परिषद की बैठक में एमआईसी जहीर अब्बास, संजू नेताम, सनीर साहू, रोहित धनकर, जमुना ठाकुर, ममता यादव, रंजीता बेनुआ, आयुक्त मोनिका वर्मा, कार्यपालन अभियंता सुनील दुबे समेत सभी विभाग प्रमुख उपस्थित थे।

लकड़ी रखने बनेगा शेड : महापौर परिषद ने मुक्तिधाम में अंतिम संस्कार के लिए निशुल्क लकड़ी उपलब्ध कराए जाने टेण्डर शीघ्र जारी करने का निर्णय लिया। वहीं मुक्तिधाम मे लकड़ी को सहेज कर रखने के लिए पांच-पांच लाख की लागत से शेड तैयार करने के लिए प्रस्ताव शासन को शीघ्र भेजने का निर्णय लिया है।

शीघ्र शुरू होगा दशहरा मैदान का सौंदर्यीकरण : महापौर परिषद की बैठक में दशहरा मैदान रिसाली को सजाने जारी निविदा दर को स्वीकृत किया है। शीघ्र ही अब मैदान का सौंदर्यीकरण होगा। दशहरा मैदान में गेट, शेड मरम्मत के अलावा लाईट और बेडमिंटन कोर्ट का निर्माण किया जाएगा।

42 प्रकरणों का अनुमोदन : महापौर परिषद ने सामाजिक सुरक्षा साहयता योजना के तहत कुल 42 प्रकरणों का अनुमोदन किया। इसमें राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजन के 23, विधवा पेंशन के 05, परिवार सहायता योजना के 11, सुखद सहारा पेंशन योजना के 01 और नवीन मुख्यमंत्री पेंशन योजना के 02 प्रकरण शामिल है।

पौधा लगाकर भूलें नहीं, वृक्ष बनने तक पालें - तभी सच्चा पर्यावरण धर्म" : विधायक ललित चन्द्राकर

एक पेड़ माँ के नाम" पौधारोपण कर विधायक ने दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग

विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर ग्राम पुरई में भारतीय जनता पार्टी, उतई मंडल द्वारा "एक पेड़ माँ के नाम" अभियान के तहत वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। दुर्ग ग्रामीण विधायक एवं छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष (कैबिनेट मंत्री दर्जा) ललित चन्द्राकर मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए।

मुख्य अतिथि ललित चन्द्राकर ने शीतला मंदिर प्रांगण एवं पुरई नसर्री में बादाम का पौधा रोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया तथा कार्यकर्ताओं के साथ करंज, नीम सहित अन्य छायादार व फलदार पौधे लगाए।

इस अवसर पर विधायक ललित चन्द्राकर ने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 'एक पेड़ माँ के नाम' आह्वान हम सबके लिए मंत्र है। लेकिन हमें सिर्फ.पेड़ लगा देना नहीं है, उसको वृक्ष बनने तक देखरेख करना है। पानी देना है, सुरक्षा देनी है। जैसे माँ हमें पालती है, वैसे ही हमें पौधे को पालना है। तभी यह अभियान सफल होगा।

मेरा क्षेत्र की जनता से हाथ जोड़कर निवेदन है आप अपने जन्मदिवस, विवाह संस्कार, सालगिरह, बच्चों के जन्मदिन पर केक काटने के साथ एक पौधा जरूर लगाएं। और संकल्प लें कि जब तक वो वृक्ष न बन जाए, उसकी जिम्मेदारी आपकी है। एक व्यक्ति, एक पेड़ यही विकसित भारत और स्वच्छ छत्तीसगढ़ की नींव है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में हम हरियाली के इस महायज्ञ में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे।

कार्यक्रम में प्रमुख रूप से उतई मंडल अध्यक्ष शीतला राजपूत, महामंत्री चंदु देवांगन, प्रवीण यदु, उतई सोसायटी अध्यक्ष फत्तेलाल वर्मा, सरपंच पुरई डोमार सिंह साहू, मचांदुर सोसायटी अध्यक्ष फलेंद्र सिंह राजपूत, सुखीत यादव,महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष विमला कामड़े, महामंत्री एकता चन्द्राकर सांसद प्रतिनिधि ममता चन्द्राकर, मंडल उपाध्यक्ष रंजना चन्द्राकर, शत्रुहन साहू, हरीश यादव कांति साहू, प्रशांत ठाकुर, हर्ष चंदेल, पंच ममता देवांगन, सतरूपा साहू, घनश्याम चन्द्राकर, लोकेश निषाद, मोतिम ठाकुर, रामरतन मेश्राम, लोकेश्वर चन्द्राकर, सचिव सुनीता निर्मलकर, करगाडीह सरपंच करण सेन सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एवं ग्रामवासी उपस्थित रहे। अध्यक्ष विमला कामड़े, महामंत्री एकता चन्द्राकर, कांति साहू, प्रशांत ठाकुर, हर्ष चंदेल, पंच ममता देवांगन, सतरूपा साहू, घनश्याम चन्द्राकर, लोकेश निषाद, मोतिम ठाकुर, रामरतन मेश्राम, लोकेश्वर चन्द्राकर, सचिव सुनीता निर्मलकर, करगाडीह सरपंच करण सेन सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एवं ग्रामवासी उपस्थित रहे।

जल-जमीन-जंगल बचाओ विषय पर ड्राइंग स्पर्धा, सैकड़ों बच्चों ने दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश

नई दृष्टिबिंदु / भिलाई

विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर अखिल भारतीय उत्कृष्ट बहुउद्देशीय संस्था के बैनर तले जल-जमीन-जंगल बचाओ विषय पर ड्राइंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें सैकड़ों बच्चों ने कैनवास के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया कि जल ही जीवन है, जमीन बचाओ ताकि वर्षा का जल भीतर जा सके और पेड़ हमारी जीवन शैली का आधार हैं।

संस्था की अध्यक्ष व सामाजिक कार्यकर्ता शानू मोहनन ने बताया कि बच्चों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक कर भविष्य के लिए तैयार करने हेतु इस आयोजन का यह 17वां वर्ष है। प्रतियोगिता में बच्चों ने दिखाया कि पर्यावरण संरक्षण केवल मानव के लिए नहीं, बल्कि पशु-पक्षी और जीव-जंतुओं के लिए भी आवश्यक है।

संयोजिका अभिलाषा ने धन्यवाद ज्ञापन में कहा कि पर्यावरण संरक्षण ड्राइंग कॉम्पिटिशन में बच्चों का सुबह 5:30 बजे उपस्थित होना अत्यंत सराहनीय प्रयास रहा।

प्रतियोगिता के परिणाम

प्राइमरी श्रेणी: प्रथम - तिथि ढावकर, द्वितीय - वान्या शुक्ला, तृतीय - प्रिषा साहनी। सांत्वना पुरस्कार युक्ता साहनी को मिला।

मिडिल श्रेणी: प्रथम - हर्षिता साहू, द्वितीय - हेजल साहू, तृतीय - लक्ष्य चंदाकर व आयुष कुमार गुप्ता।

हाईस्कूल श्रेणी: प्रथम - आद्या मिश्रा, द्वितीय - शिविका शर्मा, तृतीय - अशफिया खान।

इसके अतिरिक्त सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र व मैडल प्रदान किए गए। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि रुवाबांधा की पार्षद शीला नारखेडे थीं। इस अवसर पर संस्था के सदस्य सागरिका पाढी, अभिलाषा मिश्रा, उमा नायर, क्रिश यादव, शिव यादव, पुष्पा आदि उपस्थित रहे।

विश्व पर्यावरण दिवस : पौधे लगाना ही नहीं, उन्हें वृक्ष बनाना भी हमारा संकल्प है- धीरज बाकलीवाल

जलवायु संरक्षण और अपशिष्ट प्रबंधन को लेकर चलाऐंगे संयुक्त अभियान

रिसाली। नगर पालिक निगम रिसाली ने विश्व पर्यावरण दिवस पर विशेष कार्यशाला का आयोजन किया। जिसमें पर्यावरण संरक्षण और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन विषय को लेकर जनप्रतिनिधि व स्वच्छता ब्रांड एम्बेसेडरों ने गंभीरता पूर्वक चर्चा की। उन्होंने संयुक्त रूप से न केवल जागरूकता अभियान व धरातल पर विशेष रूप से कार्य करने पर एक मत हुए। निगम आयुक्त मोनिका वर्मा ने विशेष रूप से वक्ताओं की बातों को सुनकर निष्कर्ष और समाधान बताया।

स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और नगरीय विकास कार्यशाला का मुख्य विषय था। कार्यशाला की शुरूआत में महापौर शशि सिन्हा ने कहा कि स्वच्छता को लेकर देश का सर्वोच्च न्यायालय बेहद गंभीर है। यही वजह है कि सरकार अब नए कानून के रूप में न्यायालय के निर्देशों का पालन कर रही है। उन्होंने कार्यशाला में उपस्थित ब्रांड एम्बेसेडर और वक्ताओं से आव्हान किया कि वे अपने-अपने विधा में परांगत है। इसका फायदा सीधे तौर पर नागरिकों को पहुंचाए। उन्हें जागरूक होने के साथ-साथ यह भी बताएं कि आने वाले समय में पर्यावरण अथवा स्वच्छता से खिलवाड़ करने पर न केवल जुर्माना होगा, बल्कि कानूनी दांव पेच का अलग से सामना करना पड़ेगा। रिसाली निगम के विशेष कार्यशाला में सभापति केशव बंछोर, नेता प्रतिपक्ष शैलेन्द्र साहू, एमआईसी ममता यादव, सनीर साहू, जमुना ठाकुर, पार्षद शीला नारखेड़े ममता सिन्हा, सविता ढवस, रेखा देवी, सरिता देवांगन, ईश्वरी साहू, सीमा साहू आदि उपस्थित थे।

स्कूल से लेकर मोहल्ले तक चलेगा अभियान : कार्यशाला में ब्रांड एम्बेसेडर ने अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों को आश्वस्त किया कि वे जल्द ही स्कूल से लेकर कॉलेज और मोहल्ले में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को लेकर जागरूकता अभियान चलाऐंगे। उन्होंने मैदानी स्तर पर संयुक्त टीम के साथ भ्रमण करने की योजना भी तैयार की। विश्व पर्यावरण दिवस पर आयोजित कायर्शाला में महापौर शशि सिन्हा और आयुक्त मोनिका वर्मा ने ब्रांड एम्बेसेडर अशोक महेश्वरी, एस सजीव, रजनी रजक, डॉ. राखी राय, डॉ. डी. पी. देशमुख, प्रदीप साहू, डॉ. विपीन अरोरा, मनोज वर्मा, ललित वर्मा को परिचय पत्र देते हुए सम्मानित किया।

किया पौध रोपण : कार्यशाला के पश्चात वक्ताओं और जनप्रतिनिधि सीधे रिसाली सेक्टर पूर्व वार्ड क्र. 07 स्थित उद्यान पहुंचे। जहां पर 30 फलदार और छायादार पौध का रोपण किया। इस अवसर पर रोपे गए पौधे की देखभाल करने की जिम्मेदारी महिला समूह की सद्स्यों ने ली।

जिला कांग्रेस कमेटी दुर्ग शहर की अनूठी पहल

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग

विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी दुर्ग शहर द्वारा पर्यावरण संरक्षण एवं जनजागरण के उद्देश्य से शहर के प्रमुख मंदिरों में तुलसी के पौधे भेंट कर एक विशेष अभियान चलाया गया। अभियान की शुरुआत साईं बाबा मंदिर से की गई, जिसके पश्चात दुर्गा मंदिर, राम मंदिर, शीतला मंदिर, चंडी मंदिर सहित शहर के 11 प्रमुख मंदिरों में तुलसी के पौधे अर्पित कर पर्यावरण संरक्षण एवं प्रकृति संवर्धन का संदेश दिया गया।

इस अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी दुर्ग शहर के अध्यक्ष एवं पूर्व महापौर धीरज बाकलीवाल ने कहा कि वतर्मान समय में पर्यावरण संरक्षण केवल एक सामाजिक अभियान नहीं, बल्कि मानव अस्तित्व से जुड़ी अनिवार्य आवश्यकता बन चुका है। उन्होंने कहा कि अक्सर लोग उत्साहवश बड़ी संख्या में पौधारोपण तो कर देते हैं, लेकिन उनके संरक्षण एवं संवर्धन की जिम्मेदारी नहीं निभाते। वास्तविक पर्यावरण सेवा तभी सार्थक होगी जब लगाए गए पौधों को संरक्षित कर वृक्ष बनने तक उनका पालन-पोषण किया जाए।

श्री बाकलीवाल ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता एवं संसाधनों के अनुरूप पौधारोपण करना चाहिए तथा उनकी देखभाल का संकल्प भी लेना चाहिए। केवल पौधे लगाने से पर्यावरण सुरक्षित नहीं होगा, बल्कि उन्हें जीवित रखकर विकसित वृक्ष बनाना ही सबसे बड़ी पर्यावरणीय जिम्मेदारी है। एक विकसित वृक्ष सैकड़ों पौधों के बराबर पर्यावरण को लाभ पहुंचाता है।

इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री राजेंद्र साहू ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण केवल सरकारों या संस्थाओं की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक का नैतिक कर्तव्य है। बढ़ता प्रदूषण, घटते वन क्षेत्र और जलवायु परिवर्तन आज पूरी मानवता के समक्ष गंभीर चुनौती बनकर खड़े हैं। यदि समय रहते प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो आने वाली पीढ़ियों को इसके दुष्परिणाम भुगतने पड़ेंगे।

मुकेश राठी ने कहा कि तुलसी भारतीय परिवारों की परंपरा और संस्कृति का अभिन्न हिस्सा रही है। मंदिरों में तुलसी के पौधे अर्पित करने का उद्देश्य केवल पौधारोपण नहीं, बल्कि लोगों में पर्यावरण के प्रति भावनात्मक जुड़ाव उत्पन्न करना है ताकि वे पौधों के संरक्षण को अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी समझें।

इस अवसर पर उपस्थित कांग्रेसजनों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं ने पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण एवं वृक्षारोपण को जनआंदोलन बनाने का संकल्प लिया तथा नागरिकों से अधिक से अधिक पौधे लगाने और उनके संरक्षण की जिम्मेदारी निभाने की अपील की। कार्यक्रम के अंत में जिला कांग्रेस कमेटी दुर्ग शहर ने यह संदेश दिया कि एक पौधा लगाना पुण्य है, लेकिन उसे वृक्ष बनाना सबसे बड़ा पर्यावरण धर्म है।

पर्यावरण स्लोगन, पोस्टर व सुझाव स्पर्धा का आयोजन

5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य पर टॉपवर्थ स्टील्स एवं पॉवर प्रा. लि. रसमड़ा परिसर में वृक्षारोपण कार्यकम 2026 का शुभारंभ कारखाना प्रमुख द्वारा पौधों का रोपण कर किया गया। इस अवसर पर सेवानियुक्तों के लिए "प्रकृति से प्रेरित, जलवायु के लिए एवं हमारे भविष्य के लिए" पर्यावरण स्लोगन, पोस्टर व सुझाव प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें सेवानियुक्तों ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर प्रकृति के साथ अपनी संबंध एवं सजकता का प्रदर्शन किया। इस अवसर पर उपस्थित सेवानियुक्तों को अपने संदेश में संस्था के मुख्य परिचालन अधिकारी द्वय जय थॉमस एवं बीव्ही नारायणा ने वृक्ष की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए इस वर्ष पर्यावरण दिवस की थीम "प्रकृति से प्रेरित, जलवायु के लिए एवं हमारे भविष्य के लिए" से संस्था की सम्बंधता प्रकट करते हुए पर्यावरण संरक्षण के उपाय एवं सुझाव पर सेवानियुक्तों का ध्यान आकृष्ट किया एवं पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन पर सारगर्भित संदेश सेवानियुक्तियों को दिया।

कार्यक्रम में उपस्थित जय थॉमस, बीव्ही नारायणा, केटी टिड़के, गुंजन पोदार, बिनोद कुमार, कांति ऋषि, एमएस रेडी, मनोज महाजन, सत्येन्द्र सिंह, केपी सिंह, पवन, अप्पाराव, अभिषेक शर्मा, कमलेश पवार, विकास प्रजापति, संजय यादव, रतन साहू ओम प्रकाश साहू, सुश्री रिया, जागृति चमेली यादव सहित एवं इकाई के सेवानियुक्तों उपस्थित रहे। सभी सेवानियुक्तगण, अधिकारी, कमर्चारी व श्रमिकगण इकाई परिसर में आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में पौधों का रोपण कर हरित कांति का संदेश वतर्मान जलवायु परिवर्तन के लिए सजग रहने का संदेश सभी जनमानस तक पहुँचाने का प्रयास संदेश किया गया।

हर दीवार दे रही स्वच्छता का संदेश, रंगों में बस रही शहर की नई पहचान

दुर्ग। स्वच्छता सर्वेक्षण 2025-26 के अंतर्गत दुर्ग नगर पालिक निगम द्वारा शहर को स्वच्छ, सुंदर एवं आकर्षक बनाने के लिए व्यापक स्तर पर जागरूकता और सौन्दर्याकरण अभियान चलाया जा रहा है। शहर के प्रमुख मार्गो, सार्वजनिक स्थलों और दीवारों पर आकर्षक वॉल पेंटिंग्स तथा स्वच्छता संदेशों के माध्यम से नागरिकों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इन प्रयासों से शहर की दीवारें अब स्वच्छता का संदेश देते हुए नई पहचान बना रही हैं। नगर निगम प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे सार्वजनिक स्थानों और दीवारों पर थूकने से बचें, कचरा इधर-उधर न फैलाएं तथा स्वच्छता बनाए रखने में निगम प्रशासन का सहयोग करें। निगम का मानना है कि स्वच्छ और सुंदर शहर के निर्माण में जनभागीदारी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

महापौर अलका बाघमार ने कहा कि स्वच्छ शहर हर नागरिक की पहचान होता है और शहर को सुंदर बनाए रखने में आम जनता की भागीदारी आवश्यक है। उन्होंने बताया कि निगम द्वारा स्वच्छता सर्वेक्षण को ध्यान में रखते हुए लगातार सफाई अभियान, कचरा प्रबंधन एवं सौन्दर्याकरण कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने नागरिकों से अपने आसपास साफ-सफाई बनाए रखने और दुर्ग को देश के स्वच्छ शहरों की सूची में शामिल कराने में सहयोग करने की अपील की। आयुक्त सुमित अग्रवाल ने कहा कि नगर निगम द्वारा शहर के विभिन्न क्षेत्रों में स्वच्छता एवं सौन्दर्याकरण कार्यो की नियमित मॉनिटरिंग की जा रही है। दीवारों पर बनाई जा रही आकर्षक पेंटिंग्स और संदेश नागरिकों को स्वच्छता के प्रति प्रेरित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि निगम की टीम लगातार मैदानी स्तर पर कार्य कर रही है और स्वच्छता को जनआंदोलन का रूप देने का प्रयास किया जा रहा है।

स्वास्थ्य प्रभारी नीलेश अग्रवाल ने कहा कि स्वच्छता केवल निगम की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हर नागरिक का कर्तव्य है। यदि सभी नागरिक मिलकर शहर को साफ रखने का संकल्प लें, तो दुर्ग स्वच्छता के क्षेत्र में नई पहचान स्थापित कर सकता है। उन्होंने नागरिकों से कचरा निर्धारित स्थान पर डालने और सार्वजनिक स्थलों को स्वच्छ बनाए रखने की अपील की। नगर निगम का यह अभियान न केवल शहर की सुंदरता बढ़ा रहा है, बल्कि नागरिकों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता और जिम्मेदारी की भावना भी विकसित कर रहा है।

दाऊ के तीर, विधायक का कुर्ता, मैडम की नीयत में कचरा, शराब ने निपटाया

अंदर की बात

-:: खुलकर: :-
यशवंत साहू
फाउंडर भिलाई टाइम्स

राजनीतिक गलियारों में चल रही है चर्चा

1. जो जीजा जी कहेंगे, मैं वो करूंगा: ये डॉयलॉग तो बंधन फिल्म का है। लेकिन दुर्ग जिले के माननीय जनप्रतिनिधि के साले साहब इन दिनों यही कहते हुए घूम रहे हैं कि जो जीजा जी कहेंगे, मैं वो करूंगा...लोग जैसे ही ये लाइन सुनते हैं, उन्हें सलमान खान याद आते हैं। खैर, जीजा जी ने पूरा इलाका उनके लिए छोड़ दिया है। ठेकेदार से लेकर निगम के अधिकारी सीधे उनके द्वार पहुंचते हैं। साले साहब का पूरा काम एक फोन पर हो जाता है। पहले ठीक-ठाक जलवा था। अब जलवा कम हो गया है। लोगों ने दूरी बनानी शुरू कर दी है। कई पार्षद कहते हैं, गन्ने की जूस की तरह रस निकालकर छिलका फेंक दिए हैं। ऐसे में जीजा जी के इमेज पर तगड़ा डेंट पड़ा है। कहावत है, सारी खुदाई एक तरफ और जोरू का भाई एक तरफ। ध्यान रखना होगा, नहीं तो 28 में दिक्कत न हो जाए।

2. मंत्रिमंडल फेरबदल का फिर से हल्ला: जब राजनीतिक पंडित और ब्यूरोक्रेट्स के पास कोई काम न हो तो एक हल्ला उड़ा देते हैं। वो है मंत्रिमंडल फेरबदल का। अब ये कह रहे हैं कि चार मंत्रियों की छुट्टी होगी। सरगुजा रेंज का वजन कम किया जाएगा। सीएम साहब वहां अकेले संभाल लेंगे। अब सवाल ये है कि उस रेंज के दो मंत्रियों की कुर्सी डगमगा रही है। अब सवाल ये है कि उनकी जगह कौन लेंगे... ? क्या दुर्ग रेंज का वेट बढ़ाया जाएगा। या दुर्ग रेंज फिर से पावरफुल हो जाएगा। रायपुर वाले भी इंतजार कर रहे हैं। बस्तर रेंज को कुछ बड़ा मिलने वाला है। बस थोड़ा और इंतजार। लेकिन कब तक ? ये भी तो एक बड़ा सवाल है।

3. अडानी की वजह से हल्का हुआ पर्यावरण संदेश: लोगों के मन में सवाल है कि इस बार 5 जून को पर्यावरण दिवस इतना हल्के में कैसे मना लिए। न ताम, न झाम। ज्यादा फोटो-शोटो भी नजर नहीं आया। एक बहुत जानकार ने बहुत जोर से कहा है कि, इन सबके पीछे अडानी है। हसदेव में फिर से पेड़ों की कटाई होने वाली है। खबर सनसनी की तरह फैल गई है। भाजपा के नेता या सरकार के लोग पेड़ लगाने की बात करते हैं तो लोग उनके प्रोफाइल या फोटो-वीडियो पर जाकर कमेंट कर दे रहे हैं कि दोमुंह सांप की तरह काम न करें। एक तरफ पेड़ों की कटाई की अनुमति देते हो और यहां पेड़ लगाने का ज्ञान देते हैं। लोग अब समझ चुके हैं कि पेड़ लगाने से ज्यादा महत्वपूर्ण पेड़ों को बचाना है। कहीं न कहीं अडानी बुखार है जो उतरने का नाम नहीं ले रहा है। इस बार सादा होने के पीछे यही बड़ी वजह है। कोई बड़ा कार्यक्रम नजर नहीं आया इस बार।

4. वाह दाऊ वाह, एक तीर में दो निशाना: दाऊ जी के पास तीरों की कमी नहीं है लेकिन वो कोशिश करते हैं कि तीर का यूज कम करना पड़े। एक तीर में ही दो निशाना हो जाए, इसी फॉर्मेट में दाऊ जी काम करते हैं। दुर्ग शहर में उन्होंने अपना एक ही तीर निकाला और निशाना दो जगह पर कर दिए। दरअसल, धीरज को जिलाध्यक्ष बनाकर दाऊ ने बड़ा मैसेज दिया है कि दुर्ग शहर में वो परिवार के अलावा और कोई भी है जो राजनीत कर सकता है। जूनियर वोरा को साइलेंट करने की नीयत से धीरज को आगे किया। वहीं बीच-बीच में जूनियर वोरा की भी पूछपरख करते रहते हैं ताकि उन्हें बुरा न लगे। दुर्ग शहर के दौरे पर जब दाऊ पहुंचे तो धीरज के घर जाकर बधाई भी दिए और वोरा निवास पहुंचकर अम्मा जी का हालचाल जानकर जूनियर वोरा को संतुष्ट भी कर दिए। ये काम दाऊजी को बढ़िया आता है।

5. लोहा चोरों को किसका संरक्षण...?: भिलाई शहर में ये सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर इन लोहा चोरों को किसका संरक्षण है... ? तभी तो इनके हौंसले बुलंद थे और बिंदास भिलाई स्टील प्लांट से लोहा चुरा रहे थे। ये काफी दिनों से चल रहा है। बस अब पकड़े गए। क्योंकि, इस बार वाले कप्तान पिघले नहीं। इनको ही निपटा दिए। अब संरक्षण देने वाले नेताओं की चिंता बढ़ गई है। कहीं वो फोनकॉल से पता न चल जाए कि लोहा चोरों से डायरेक्ट बात होती है। वैसे इन्हें संरक्षण देने वाले दोनों ही दलों में है। तभी तो लोहा चोरों संग इन नेताओं की तस्वीर है। बकायदा, निवास आना-जाना होता है और बड़े कार्यक्रमों में तगड़ी फंडिंग कर सारा इंतजाम भी करते हैं। नेता जी चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये मामला शांत हो। ताकि चैन की नींद ले सकें। फिलहात सब चिंता में है कि कहीं उनके द्वारा दिए गए संरक्षण का पुलिंदा बाहर न खुल जाए।

6. मेयर की नीयत में कचरा: गजब हो मैडम, पहले विरोध, अब उसी का सपोर्ट...पूरा खेल तो कमीशन का है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, वो सब लोग कह रहे हैं, जिन्होंने मेयर मैडम के आंदोलन को सपोर्ट किया था। मैडम जी, बेहोश हो गई थीं प्रदर्शन में। पार्षदों ने उठाकर अस्पताल पहुंचाया। दो महीने बाद मैडम और उनकी एमआईसी ने ही सफाई ठेके एक्सटेंशन वाली फाइल को मूव करते हुए एप्रूवल दे दिया। गजब है भाई। लोग पूछ रहे हैं कि मैडम जी का कमीशन फिर से सेट हो गया क्या ? तभी तो करोड़ों की सफाई ठेके वाली फाइल को पूरी एमआईसी ने मिलकर ओके कर दिया। इसीलिए लोग कह रहे हैं कि मैडम की नीयत में ही कचरा है। ये मामला तूल पकड़ने वाला है। क्योंकि अब उनके धूर विरोधी कई भगत हैं जो इसी मौके की ताक पर थे। अब फेस करिएगा आरोपों की झड़ी। वो भी बिन बारिश वाली।

7. सिर्फ रायगढ़ ही नहीं, प्रदेशभर में ओपी का जलवा: छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने तीन से चार दिनों तक जन्मदिन मनाया। जन्मदिन के एक दिन पहले से रायगढ़ पहुंचे। फिर सुबह से देर रात तक रायगढ़वासियों संग जन्मदिन मनाया। अगले दिन मंत्रीजी रायपुर पहुंच गए। यहां भी रायगढ़ जैसा उत्साह और माहौल। ओपी का जलवा देख एक नेता जी ने कह डाला कि इनका काम बढ़िया है गुरू। हर क्षेत्र में तगड़ा। कार्यकर्ताओं में गजब उत्साह है। दो-तीनों का जन्मदिन हो गया। यानी कि सब बढ़िया चल रहा है। ओपी ने ये सब मेंटेन खुद ही किया। कामों की पेंडेंसी रखते नहीं है। एक हाथ में फोन रहता है। लोगों की समस्या सुनते ही कलेक्टर, एसपी, सेक्रेटरी के पास खुद ही फोन लगाकर बात करते हैं। सीधा संवाद का गजब फॉर्मूला है। बहुत जल्द कुछ बड़ा करने वाले हैं। सबको टेंशन है कि ओपी के तीर का निशाना किसे लगने वाला है। सीधे दिल्ली रिपोर्टिंग होती है। सो स्टेट के बाकी नेता और अफसर उन्हें हल्के में नहीं लेते और न ही उन्हें एक्सक्यूज का पाठ पढ़ाते हैं। सीधे काम करते हैं। ये जलवा है ओपी का।

8. शराब दुकान ने भाजपा को निपटा दिया: राजनांदगांव यानी कि रमन का गढ़। अब भाजपा यहां चुनाव हार जाए ये तो हेडलाइन ही होगी न... ? बहुत लोगों ने इसी हेडिंग के साथ खबरें कवर की। ये बात अलग है कि रमन चुनाव प्रचार में घूमका नगर पंचायत नहीं गए। उनकी कोर टीम ने मोर्चा संभाला था। लेकिन करारी हार मिली। मंथन हुआ परिणाम के बाद। पता चला कि भूपेश बघेल ने जहां गौठान बनाया था, वहां आबकारी विभाग के अधिकारियों ने बड़े साहब यानी प्रशासनिक मुखिया से पूछकर शराब दुकान खुलवा दिया। यही बात और काम भारी पड़ा। अब कलेक्टर साहब से पूछा जा रहा है कि ये किसका फैसला था कि गौठान में शराब दुकान खुले... ? साहब के पास जवाब तो बहुत है। लेकिन स्पष्ट नहीं है। खैर दुकान तो खुल गई और चुनाव भी हार गए। भले ही भाजपा सरकार को यहां से वोट नहीं मिला, लेकिन शराब दुकान से राजस्व तगड़ा मिलेगा। जैसे कि डोंगरगढ़ के पास चारभाठा गांव से मिलेगा। यहां भी गांव वाले भारी खुश हैं। कलेक्टर साहब को धन्यवाद लेटर तक लिख दिए गांव वालों ने। गजब है साहब, आपका भी काम।

9. पांडेय जी इज बैक: 9 जून को छत्तीसगढ़ में भाजपा के चाणक्य कहे जाने वाले और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेमप्रकाश पांडेय का जन्मदिन है। लोग कह रहे हैं कि पांडेय इज बैक। क्योंकि, इस बार जन्मदिन बहुत मायनों में खास है। इस बार होर्डिंग्स तगड़ी है। भंडारा से लेकर बहुत सारे नेक कार्य होने वाले हैं। इसकी तैयारी पूरी हो गई है। उनके समर्थक चाहते हैं कि इस बार हम भी बता देंगे कि हम भी किसी से कम नहीं है। अब बस एक दिन का इंतजार है। वैसे पूरा शहर इस चीज का इंतजार कर रहा है। सेक्टर-5 वाले नेताजी की चिंता बढ़ गई है कि अब क्या होने वाला है ?

10. कुर्ता फाड़ पॉलिटिक्स...: युवा विधायक देवेंद्र यादव के हर काम की चर्चा होती ही है। काम ही ऐसा करते हैं कि लोग चर्चा किए बगैर रह नहीं सकते। भले ही निगेटिव हो या पॉजिटिव। अब उनके कुर्ते पर सियासत हो रही है। क्या देवेंद्र ने बिलासपुर के प्रदर्शन में कुर्ता खुद ही फाड़ा या पुलिसकर्मियों के साथ झूमाझटकी में फटा... ? ये सवाल है। भाजपा ने अपने ऑफिशियल पेज से वीडियो शेयर करते हुए दावा कर दिया कि देवेंद्र ने खुद ही कुर्ता फाड़ दिया। अब लोग कह रहे हैं कि कुर्ता फाड़कर बस पर चढ़ने की क्या जरूरत थी... ? इस सवाल का जवाब युवा विधायक ही देंगे। वैसे आपको बता दें कि देवेंद्र के कंधे पर एफआईआर का एक और मेडल चढ़ गया है। उनके समर्थक इसे मेडल ही मानते हैं।

किसानों को खाद-बीज की कोई कमी न हो, छोटे किसानों को मिले प्राथमिकता : मुख्यमंत्री साय

पेयजल समस्या के लिए तेल नदी पर एनीकट निर्माण के लिए 7 करोड़ रुपये स्वीकृत, अवैध रेत उत्खनन पर कड़ी कार्रवाई

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि किसानों को खाद और बीज की उपलब्धता में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। छोटे और सीमांत किसानों को प्राथमिकता के आधार पर खाद-बीज उपलब्ध कराया जाए तथा इसकी जवाबदेही संबंधित कलेक्टरों की होगी। मुख्यमंत्री ने कृषि अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे गांव-गांव जाकर किसानों को नैनो यूरिया और नैनो डीएपी के लाभों की जानकारी दें ताकि आधुनिक कृषि तकनीकों का अधिकतम उपयोग हो सके। उन्होंने अवैध रेत उत्खनन के विरुद्ध तत्काल और प्रभावी कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री श्री साय गरियाबंद जिला पंचायत कार्यालय के सभाकक्ष में रायपुर संभाग के जिलों की संभागीय समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। लगभग साढ़े तीन घंटे तक चली इस मैराथन समीक्षा बैठक में रायपुर, गरियाबंद, धमतरी, महासमुंद और बलौदाबाजार जिलों के कलेक्टरों, पुलिस अधीक्षकों तथा वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विकास योजनाओं, कानून-व्यवस्था, जनकल्याणकारी कार्यक्रमों और प्रशासनिक व्यवस्थाओं की विस्तृत समीक्षा की गई। उन्होंने गरियाबंद जिले के सुपेबेड़ा क्षेत्र में पेयजल समस्या के स्थायी समाधान के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए तेल नदी पर एनीकट निर्माण हेतु 7 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की। उन्होंने कहा कि लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और पेयजल जैसी समस्याओं का स्थायी समाधान सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शासन द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि आम नागरिकों को योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होनी चाहिए तथा प्रशासन के प्रति जनता की शिकायतों को न्यूनतम स्तर पर लाने के लिए संवेदनशीलता और जवाबदेही के साथ कार्य किया जाए। उन्हों ने राजस्व प्रकरणों के त्वरित निराकरण, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में तेजी लाने, टीबी मुक्त पंचायतों के निर्माण, आयुष्मान कार्डो का शत-प्रतिशत कवरेज सुनिश्चित करने, जल जीवन मिशन के कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण करने तथा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के पात्र हितग्राहियों को लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए।

समीक्षा बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आयुष्मान भारत योजना, जल जीवन मिशन, बिहान, तेंदूपत्ता संग्रहण, महतारी वंदन योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि तथा धान उपार्जन एवं उठाव की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि आयुष्मान कार्ड बनाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि पात्र नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण उपचार और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जानी चाहिए। शिक्षा की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने स्कूलों में सीखने के स्तर में सुधार, नियमित मॉनिटरिंग तथा नवाचार आधारित शिक्षण पद्धतियों को बढ़ावा देने पर बल दिया। उन्होंने निर्देश दिए कि जिन विद्यालयों में विषय विशेषज्ञ शिक्षकों की कमी है, वहां कृत्रिम बुद्धिमत्ता (अक) आधारित तकनीकों का उपयोग कर शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाया जाए।

मुख्यमंत्री ने कानून-व्यवस्था, सड़क सुरक्षा और देश में लागू नए तीन आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन की भी समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि नए कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएं, व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाया जाए तथा सड़क सुरक्षा नियमों के पालन और नशा मुक्ति अभियान को भी प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाया जाए। बैठक में विधायक रोहित साहू, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के विशेष सचिव रजत बंसल, रायपुर संभागायुक्त श्याम धावड़े, आईजी अमरेश मिश्रा सहित संबंधित जिलों के जनप्रतिनिधि एवं वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री साय ने ऐतिहासिक चतुर्भुज विष्णु मंदिर में की पूजा-अर्चना

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सुशासन तिहार के अंतर्गत सक्ती जिले के जैजैपुर विकासखंड स्थित ग्राम ठठारी पहुंचकर ऐतिहासिक चतुर्भुज विष्णु मंदिर में विधि-विधान से पूजा-अर्चना की। मुख्यमंत्री श्री साय ने भगवान विष्णु से प्रदेशवासियों के सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और खुशहाली की कामना करते हुए छत्तीसगढ़ के सर्वांगीण विकास के लिए आशीर्वाद मांगा। यह प्राचीन मंदिर क्षेत्र की आस्था, संस्कृति और ऐतिहासिक विरासत का महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। स्थानीय जनश्रुतियों के अनुसार यहां स्थापित भगवान विष्णु की प्रतिमा चौथी शताब्दी की मानी जाती है, जो इस स्थल की ऐतिहासिक महत्ता को और अधिक विशेष बनाती है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय लगातार प्रदेश के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। इसी क्रम में मुख्यमंत्री श्री साय ग्राम ठठारी में आयोजित जनचौपाल में भी शामिल हुए, जहां उन्होंने ग्रामीणों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं तथा शासन की योजनाओं के लाभांवितों से चर्चा कर व्यवस्थाओं की वास्तविक स्थिति की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को जनसमस्याओं के त्वरित और संवेदनशील निराकरण के निर्देश दिए। इस अवसर पर जांजगीर-चांपा लोकसभा क्षेत्र की सांसद श्रीमती कमलेश जांगड़े, मुख्यमंत्री के विशेष सचिव रजत बंसल, कलेक्टर अमृत विकास तोपनो, पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल ठाकुर सहित जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित थे।

उप मुख्यमंत्री शर्मा ने राष्ट्रीय पदक विजेता बेसबॉल खिलाड़ियों का किया सम्मान

रायपुर। ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित 31वीं राष्ट्रीय सब जूनियर बेसबॉल बालक एवं बालिका प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर प्रदेश का गौरव बढ़ाने वाले कवर्धा के खिलाड़ियों से उप मुख्यमंत्री एवं विधायक कवर्धा विजय शर्मा ने अपने कवर्धा स्थित निवास कार्यालय में मुलाकात कर उन्हें उनके उज्वल भविष्य की कामना की।

एमेच्योर बेसबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वावधान में 24 से 29 मई तक आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रयास स्पोर्ट्स अकादमी कवर्धा के पांच खिलाड़ियों का छत्तीसगढ़ टीम में चयन हुआ था। इनमें बालक वर्ग से चंद्रेश कोर्राम, पंकज मेरावी और शुभम सेन तथा बालिका वर्ग से चांदनी साहू और जयश्री घृतलहरे शामिल थीं। प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ की बालक टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक हासिल किया, जबकि बालिका टीम ने रजत पदक जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने खिलाड़ियों को बधाई देते हुए कहा कि ग्रामीण अंचलों से निकलकर राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करना पूरे प्रदेश के लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने और उन्हें बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयासरत है। खिलाड़ियों की यह सफलता आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा बनेगी। अकादमी के प्रशिक्षक राजा जोशी ने बताया कि खिलाड़ियों का चयन राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर हुआ था। राष्ट्रीय प्रतियोगिता के दौरान छत्तीसगढ़ की बालक टीम ने मध्यप्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, राजस्थान और दिल्ली जैसी मजबूत टीमों को हराकर फाइनल में महाराष्ट्र को 6-2 से पराजित कर राष्ट्रीय खिताब अपने नाम किया। फाइनल मुकाबले में चंद्रेश कोर्राम ने शानदार होमरन लगाकर टीम की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

शिवाजी महाराज के आदर्श आज भी युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत - राज्यपाल

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

राज्यपाल रमेन डेका ने महाराष्ट्र मंडल रायपुर में छत्रपति शिवाजी महाराज राज्याभिषेक समारोह दिवस में उनकी प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज का जीवन साहस, स्वाभिमान, सुशासन और राष्ट्रभक्ति का अद्वितीय उदाहरण है, जो आज भी युवा पीढ़ी को प्रेरणा देता है।

राज्यपाल ने कहा कि 6 जून 1674 को रायगढ़ दुर्ग में हुआ शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक केवल एक राजतिलक नहीं, बल्कि स्वतंत्र हिंदवी स्वराज की स्थापना का ऐतिहासिक क्षण था। उन्होंने कहा कि शिवाजी महाराज ने अपने पराक्रम, दूरदर्शिता और कुशल नेतृत्व से स्वराज की मजबूत नींव रखी तथा करोड़ों भारतीयों में आत्मसम्मान और आत्मविश्वास का संचार किया। उन्होंने शिवाजी महाराज को कुशल प्रशासक, प्रजावत्सल शासक और धार्मिक सहिष्णुता का प्रतीक बताते हुए कहा कि उनके द्वारा स्थापित अष्टप्रधान व्यवस्था, संगठित नौसेना तथा जनकल्याणकारी नीतियां आज भी प्रासंगिक हैं। राज्यपाल ने महाराष्ट्र मंडल की 91 वर्षों की गौरवशाली सेवा यात्रा की सराहना करते हुए कहा कि संस्था द्वारा संचालित विभिन्न सामाजिक और शैक्षणिक प्रकल्प समाज सेवा की उत्कृष्ट मिसाल हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि महाराष्ट्र मंडल भविष्य में भी समाज और राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देता रहेगा।

श्री डेका ने कार्यक्रम में शानदार सांस्कृतिक प्रस्तुति देने वाले चार बच्चों को पांच -पांच हजार रुपए की राशि पुरस्कार स्वरूप प्रदान की तथा महाराष्ट्र मंडल को एक एंबुलेंस प्रदान करने की भी घोषणा की। इस अवसर पर महापौर श्रीमती मीनल चौबे, महाराष्ट्र मंडल रायपुर के अध्यक्ष अजय मधुकर काले सहित अन्य पदाधिकारी एवं महाराष्ट्रीयन समाज के लोग बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

पीएम आवास पूणर्ता में पूरे देश में सबसे आगे छग, ढाई सालों में 10 लाख से अधिक आवास पूरे - उप मुख्यमंत्री शर्मा

बोड़ला क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार, तरेगांव में 2.50 करोड़ से बनेगा सीएचसी, राजा नवागांव में 75 लाख से अपग्रेड होगा सब सेंटर

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर-कबीरधाम

उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा कबीरधाम जिले के बोड़ला नगर पंचायत में आयोजित सुशासन तिहार में शामिल हुए। यहां उन्होंने क्षेत्रवासियों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को निराकरण के निर्देश दिये। शिविर के दौरान उन्होंने विभिन्न हितग्राहियों को शासन की योजनाओं से लाभान्वित भी किया।

शिविर को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने अपने उद्बोधन में कहा कि बीते दिनों यहां 7 करोड़ रुपए के विभिन्न कार्यों का भूमिपूजन लोकार्पण किया गया है। 1.5 करोड़ की लागत से यहां तालाब के सौंदर्यीकरण की स्वीकृति मिली है। जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में हुए कार्यो का उल्लेख करते हुए कहा कि अन्य काम दस बीस सालों के लिये होते हैं लेकिन मेडिकल कॉलेज जैसा काम सौ साल का होता है। उन्होंने बताया कि काम तेजी से हो रहा है। हर शुक्रवार निर्माण कार्य में हुई प्रगति का अपडेट लिया जाता है। उन्होंने कहा कि बोड़ला क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए निरंतर प्रयास हो रहे हैं। तरेगांव जंगल के पीएचसी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उन्नयन के लिए 2.50 करोड़ की स्वीकृति मिली है। राजा नवागांव सब सेंटर 75 लाख की लागत से पीएचसी में अपग्रेड होने जा रहा है।

उन्होंने बताया कि भोरमदेव कॉरिडोर में मंदिर परिसर, मड़वा महल, छेरकी महल, रामचुंवा के साथ सरोदा बांध का उन्नयन किया जा रहा है। भोरमदेव मंदिर के इतिहास से पर्यटकों को परिचित कराने के लिए संग्रहालय का निर्माण, सरोवर का सौंदर्यीकरण, कांवड़ियों के लिए विश्राम स्थल जैसी सुविधाओं के विकास की काययीजना है। इसके लिए स्वदेश दर्शन योजना से 146 करोड़ रुपए मिले हैं। यह न सिर्फ क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देगा बल्कि पर्यटकों के आने से क्षेत्रवासियों के लिए आर्थिक विकास की राह भी खोलेगा। किसानों की सुविधा के लिए बोड़ला में ट्रांसफार्मर अपग्रेडेशन का काम किया जा रहा है। नया सब स्टेशन का काम चल रहा है। फीडर अलग करने का काम भी जारी है। घरेलू कनेक्शन और खेतों में गया फीडर अलग किया जा रहा है। ताकि विद्युत आपूर्ति सुचारु रहे।

लोरमी विधायक धमर्जीत सिंह ने कहा कि प्रदेश के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के नेतृत्व में इस पूरे क्षेत्र के समुचित विकास की ठोस आधारशिला रखी जा रही है जिसका लाभ आने वाली पीढ़ियों को भी मिलेगा। उनके मार्गदर्शन में कवर्धा में स्वास्थ्य सुविधाओं में उल्लेखनीय विस्तार हुआ है। यहां मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है। जिसका लाभ पूरे जिले के मरीजों को मिलेगा। जिला अस्पताल में सीटी स्कैन और सोनोग्राफी जैसी सुविधाएं मिल रही हैं। अटल आरोग्य लैब से कई प्रकार की जांच निःशुल्क होती है। उनके नेतृत्व में भोरमदेव कॉरिडोर का निर्माण होने जा रहा है। यह परियोजना भोरमदेव मंदिर को देश के पर्यटन मानचित्र पर मजबूती अंकित करने का रहा है। यह सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं होगा बल्कि क्षेत्र के आर्थिक विकास को भी आगे बढ़ाएगा। उन्होंने नक्सल उन्मूलन पर बात करते हुए कहा कि यह मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व और उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा के संकल्प और सतत प्रयासों से संभव हुआ है।

पीएम जनमन से बैगा बसाहटों को जोड़ने बन रही 56 सड़कें : पीएम जनमन से प्रदेश की 2.25 लाख विशेष पिछड़ी जनजाति के लिए करीब 800 सड़कें बनाई गई। जिले में बैगा बाहुल्य बसाहटों के 56 सड़कें बन रही हैं, जिनमें से अधिकांश सड़कें पूरी हो चुकी हैं। पीएमजीएसवाय फेज-4 से बोड़ला विकासखंड में 16 सड़कें बन रही हैं। विभिन्न सड़कों का नवीनीकरण किया जा रहा है। दूरस्थ अंचलों को बारहमासी सड़क संपर्क से जोड़ने के लिए विशेष रूप से काम किया जा रहा है। इसके साथ ही पीएम जनमन योजना से शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, महिला एवं बाल विकास के साथ अन्य महत्वपूर्ण योजना का लाभ पहुंचाने का काम हो रहा है। जिससे जिले में निवासरत विशेष पिछड़ी जनजाति बैगाओं का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित हो।

2.5 वर्षों में पूरे देश में सर्वाधिक आवास किये पूरे : उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने बताया कि सरकार गठन के बाद पीएम आवास निर्माण की स्वीकृति और उसे पूर्ण करने का काम पूरी तेजी से किया गया। उन्होंने बताया कि बीते 2.5 वर्षों में पूरे प्रदेश में 10 लाख 60 हजार पीएम आवास पूरा किया है। यह इस अवधि में पूरे देश में सर्वाधिक है। जनवरी 2025 से अक्टूबर तक प्रदेश में 2 हजार आवास प्रतिदिन पूर्ण हो रहे थे। यह देश में सबसे अधिक था। आज भी देश में सबसे ज्यादा 1600 आवास प्रतिदिन पूरा किया जा रहा है। शहरी क्षेत्रों में भी आवास निर्माण की गति बढ़ाई जा रही है।

उप मुख्यमंत्री ने सौंपी आवास की चाबी, हितग्राहियों को किया लाभन्वित : सुशासन तिहार के दौरान उप मुख्यमंत्री ने विभिन्न हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ प्रदान किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को नए आवास की चाबी सौंपी गई। इसके साथ ही उप मुख्यमंत्री द्वारा नवीन राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, एचआईवी वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र का भी वितरण किया। साथ ही कार्यक्रम में शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया एवं उनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं।

समाधान शिविर में जिला पंचायत अध्यक्ष ईश्वरी साहू, नगर पंचायत अध्यक्ष बोड़ला विजय पाटिल, जनपद पंचायत अध्यक्ष बोड़ला श्रीमती बालका राम किंकर वर्मा, उपाध्यक्ष नंद श्रीवास, नितेश अग्रवाल, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष विदेशी राम धुर्वे सहित अन्य जनप्रतिनिधि और ग्रामवासी उपस्थित रहे।

संपादकीय

निकाय चुनाव का संदेश साफ है, राज्य में सुशासन है

जनता सरकार के प्रति कैसी सोच रखती है, जनता विपक्ष के प्रति कैसी सोच रखती है। क्या जनता सरकार से नाराज है, क्या जनता विपक्ष के काम से खुश है। क्या जनता सरकार से ज्यादा पसंद विपक्ष को करती है,क्या जनता अगले चुनाव में सत्तारूढ़ दल को हटाकर विपक्ष को मौका देना चाहती है। इसका एक ही पैमाना है चुनाव में जनता ने किसको ज्यादा पसंद किया। चुनाव में उसकी पहली पसंद क्या है। चुनाव में ज्यादा प्रत्याशी किसके जीते। हाल ही में हुए निकाय चुनाव के परिणाम से साफ है कि जनता साय सरकार के कामकाज से खुश है, वह मानती है कि राज्य में साय सरकार ने सुशासन कायम है। सुशासन तिहार के माध्यम से लोगों की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। साय सरकार पर जनता ने जो भरोसा विधानसभा चुनाव में जताया था, वह भरोसा आज भी कायम है।

राज्य की पांच नगर पंचायतों के चुनाव परिणाम के अनुसार तीन में भाजपा के अध्यक्ष जीते हैं और दो में कांग्रेस के अध्यक्ष विजयी रहे हैं। इसी तरह 71 पार्षद पदों के लिए चुनाव में भाजपा समर्थित प्रत्याशी 39 पदों पर,कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी 30 सीटों पर विजयी रहे हैं साथ ही दो प्रत्याशी निदर्लीय जीते हैं। पांच नगर पंचायतों में से चार तो नवगठित नगर पंचायत थे,और एक नगर पंचायत में अध्यक्ष का उपचुनाव कराया गया था। चार नवगठित नगर पंचायत बम्हनीडीह, शिवनंदनपुर में भाजपा तथा सहसपुर लोहारा उपचुनाव में भाजपा का प्रत्याशी विजयी रहा वहीं कांग्रेस घुमरा व पलारी में विजयी रही। सहसपुर लोहारा सीट भाजपा की थी और उपचुनाव में भाजपा अपनी सीट बचाने में सफल रही। चार नवगठित नगर पंचायतों में से भाजपा व कांग्रेस दो दो जीतने में सफल रहे। वार्डस्तर व अध्यक्ष स्तर पर चुनाव में जनादेश कई जगह विपरीत भी रहा है। घुमका अध्यक्ष कांग्रेस का जीता लेकिन यहां 15 में से 11 वार्ड में भाजपा के पार्षद जीते हैं ।वही शिवनंदनपुर में अध्यक्ष भाजपा की जीती तो यहां 15 में आठ पार्षद कांग्रेस के विजयी रहे हैं। सहसपुरलोहारा चुनाव जीतना भाजपा के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न था और वह जीत गई। बम्हनीडीह में भाजपा का दबदबा रहा। यहां अध्यक्ष पद के साथ ही 15 में 11 वार्ड में भाजपा प्रत्याशी विजयी रहे।

लोकतंत्र में तो संख्या से इस बात का फैसला होता है कि जनता की नंबर वन पसंद कौन है और नंबर दो पसंद कौन है। नगर निकाय चुनाव में अध्यक्षों की संख्या के आधार पर देखा जाए तो ज्यादा अध्यक्ष भाजपा के चुने गए हैं, इसलिए यह साफ कहा जा सकता है कि अध्यक्ष संख्या के हिसाब से जनता की पहली पसंद भाजपा और पाषर्दो की संख्या के आधार पर देखा जाए तो भाजपा के 39 पार्षद जीते है और कांग्रेस के 30 पार्षद जीते हैं, इससे भी साफ हो नगर निकाय चुनाव में जनता की पहली पसंद भाजपा बनी हुई है और कांग्रेस उसकी दूसरी पसंद है। इस हिसाब से देखा जाए तो जनता का मन विधानसभा चुनाव के बाद ढाई साल हो गए है और बदला नहीं है। वह आज भी साय सरकार के कामकाज से संतुष्ट है, वह मानती है कि साय सरकार राज्य में अच्छा काम कर रही है। उसने चुनाव में किए वादे पूरे किए है, उसकी योजनाओं का लाभ पंचायत,नगर पंचायत स्तर तक लोगों को मिल रहा है।

नगर निकाय चुनाव के बाद सीएम साय ने कहा है कि प्रदेश के विभिन्न नगर पंचायतों के चुनाव में भाजपा को ज्यादा जनसमर्थन मिला है, इससे साफ हो जाता है कि भाजपा प्रत्याशियों की विजय सरकार के सुशासन,विकास व जनकल्याणकारी नीतियों के प्रति अटूट विश्वास का स्पष्ट प्रमाण है। इससे साफ हो जाता है कि जनता विकास,पारदर्शी प्रशासन व जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देने वाली सरकार के साथ है। वहीं भाजपा अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने कहा है कि यह जीत राज्य सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों के प्रति जनता के विश्वास का परिणाम है। चुनाव में जनता के सामने भाजपा व कांग्रेस में किसी एक नंबर वन चुनना था और जनता ने साफ कर दिया है कि उसके लिए आज भी नंबर वन पसंद वाली पार्टी भाजपा है क्योंकि भाजपा ने दो साल जनहित के बहुत काम किए है, वादे पूरे किए है,जहां भी सुधार की जरूरत थी वहां सुधार किए हैं और इसका लाभ उसे चुनाव में मिला है।

वही कांग्रेस के प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के सुशील आनंद शुक्ला का नगर निकाय के चुनाव परिणाम पर कहना है कि जनता ने भाजपा के कुशासन को नकार दिया है,नगर निकाय के चुनाव परिणाम से साफ है कि प्रदेश की जनता भाजपा सरकार के ढाई साल के कामकाज से नाराज है। विधानसभा चुनाव 28 पहले सरकार के खिलाफ जनता की नाराजगी सामने आ रही है। कांग्रेस विपक्ष में है वह तो वही देखेगी जो उसे देखना है। वह तो आए दिन कहती रहती है कि सरकार हर क्षेत्र में फेल है ऐसा होता तो कांग्रेस नगर निकाय की दो नहीं पांच पांच जीत जाती, जनता में सरकार के प्रति नाराजगी होती है तो वह कोई भी चुनाव है उसके माध्यम से जनता प्रकट करती है। नगर निकाय चुनाव के परिणाम से साफ है कि जनता भाजपा सरकार से नाराज नहीं है कम से कम इतनी नाराज तो नहीं है कि जिस कांग्रेस को उससे सत्ता से हटाया था उसे फिर ढाई साल में ही सत्ता के लायक समझेगी। जो विपक्ष में होता है वह सपने देखता रहता है कि सरकार से जनता नाराज है और अगले चुनाव में जनता हमको सत्ता सौपंगी । कांग्रेस विपक्ष में है, उसे सत्ता के सपने देखने का पूरा अधिकार है।

त्रिभाषा विवाद के यक्ष प्रश्न और कोर्ट से उम्मीदें

प्रमोद जोशी

सुप्रीम कोर्ट ने गत 27 मई को सीबीएसई की उस नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने पर सहमति जताई है, जिसमें 1 जुलाई से कक्षा 9 के छात्रों के लिए दो भारतीय मूल भाषाओं सहित तीन भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य किया गया है। नई शिक्षा नीति के तहत स्कूलों में भाषाओं के अध्ययन से जुड़े कुछ सबसे महत्वपूर्ण सवाल उच्चतम न्यायालय के सामने उठे हैं। इनके पीछे दक्षिण में हिंदी बनाम विदेशी भाषा के मसले भी हैं। अभिभावकों की व्यावहारिक समस्याएं, विद्यालयों के पास उपलब्ध संसाधनों और अध्यापकों की संख्या जैसे सवालों का पिटारा भी अब खुलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने गत 27 मई को सीबीएसई की उस नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने पर सहमति जताई है, जिसमें 1 जुलाई से कक्षा 9 के छात्रों के लिए दो भारतीय मूल भाषाओं सहित तीन भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य किया गया है।

हालांकि, मुख्य न्यायाधीश सूयकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और विपुल एम पंचोली की पीठ ने इस मामले में कोई अंतरिम आदेश जारी नहीं किया है, पर उन्होंने केंद्र सरकार, सीबीएसई और एनसीईआरटी को नोटिस जारी करके दो सप्ताह के भीतर विस्तृत जवाब मांगा है। अदालत ने अलबत्ता यह कहा है कि बोर्ड का तीसरी भाषा को शामिल करने का निर्णय सिद्धांत रूप में ह्यप्रशंसनीयह्न हो सकता है, लेकिन इसे वतर्मान शैक्षणिक वर्ष से लागू करने में कुछ व्यावहारिक प्रश्न उठेंगे। शिक्षकों और पुस्तकों की कमी के मद्देनजर इस नीति को लागू करने की तार्किक और तथ्यात्मक चुनौतियों को लेकर अदालत अधिक चिंतित है।

बहरहाल, न्यायालय 15 और 16 जुलाई को दलीलें सुनेगा। उसी समय इस आदेश को लागू किया जा रहा होगा। शैक्षिक-प्रश्न के अलावा यह राजनीतिक प्रश्न भी है। अपनी भाषा-नीति के अनुरूप डीएमके ने इस कदम का विरोध किया है, वहीं कांग्रेस ने बिना परामर्श के अधिसूचना जारी होने की आलोचना की है। दक्षिण भारत, खासतौर से तमिलनाडु में कहा जा रहा है कि सीबीएसई का यह आदेश हिंदी थोपने का प्रयास है।

कुछ समय पहले, सीबीएसई ने घोषणा की थी कि तीसरी भाषा की अनिवार्यता को 2029-30 शैक्षणिक वर्ष तक स्थगित कर दिया जाएगा। यह अचानक बदलाव क्यों? एनईपी 2020, जिसके तहत यह आदेश लागू किया जा रहा है, लचीलेपन का वादा करती है। वह गारंटी देती है कि किसी भी छात्र या राज्य पर कोई भाषा थोपी नहीं जाएगी। दूसरी तरफ अभिभावक और शिक्षक बोर्ड परीक्षाओं से ठीक पहले छात्रों पर बढ़ते दबाव को लेकर चिंतित हैं। प्रशिक्षित भाषा शिक्षकों की कमी और उपयुक्त पाठ्य-पुस्तकों की अनुपलब्धता भी चुनौतियां हैं।

इस आदेश के विरोधी यह भी कहते हैं कि इससे विदेशी भाषा की पढ़ाई करने के इच्छुक छात्रों का अहित होगा। कुछ छात्र पहले से ही फ्रेंच, जर्मन या जापानी जैसी विदेशी भाषाओं का अध्ययन कर रहे हैं। वहीं इस नीति के समर्थक कहते हैं कि स्कूली शिक्षा भारतीय भाषाओं से ऊपर विदेशी भाषाओं को रखना न तो तार्किक है और न ही लाभकारी। विदेशी भाषाओं को वैकल्पिक विषयों के रूप में पढ़ाया जा सकता है। भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देना, विदेशी भाषाओं को हतोत्साहित करना नहीं है।

याचिकाकर्ताओं के वकील कपिल सिब्बल ने अदालत में कहा कि यह मुद्दा संघवाद और भाषा के चयन से जुड़े संवैधानिक अधिकारों से जुड़ा है। भाषा व्यक्तिगत पसंद का विषय है और इसे थोपा नहीं जा सकता। इस पर पीठ ने कहा कि इस तर्क को उलट कर यह कहा जा सकता है कि अधिक भाषाएं सीखना संघवाद की भावना को लाभ पहुंचाने का काम करेगा। 15 मई को जारी परिपत्र के अनुसार, विदेशी भाषा का चयन करने वाले छात्र दो भारतीय मूल भाषाओं का अध्ययन करने के बाद केवल तीसरी भाषा के रूप में या एक अतिरिक्त चौथी भाषा के रूप में ही ऐसा कर सकेंगे। यह नियम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और स्कूल शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा 2023 का हिस्सा है। परिपत्र के अनुसार कक्षा 10 में तीसरी भाषा के लिए कोई बोर्ड परीक्षा नहीं होगी। ह्यआर3 (तीसरी भाषा) के सभी मूल्यांकन पूरी तरह से विद्यालय-आधारित और आंतरिक होंगे। इसका विवरण सीबीएसई प्रमाणपत्र में परिलक्षित होगा। इस नीति के आलोचक मानते हैं कि हिंदी भाषी राज्यों ने तीन-भाषा नीति के प्रति उदासीन रुख अपनाया है, जिनमें से ज्यादातर ने क्षेत्रीय भाषा के बजाय संस्कृत को चुना है। उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान में पहली भाषा अंग्रेजी, दूसरी हिंदी और तीसरी भाषा संस्कृत है।

मध्य प्रदेश में अभी दो-भाषा नीति लागू है, जिसमें अंग्रेजी पहली भाषा और हिंदी दूसरी भाषा है। झारखंड में तीसरी भाषा मुख्य रूप से संस्कृत है, हालांकि कुछ स्कूलों में संथाली जैसी क्षेत्रीय भाषाएं भी पढ़ाई जाती हैं। इसी प्रकार, छत्तीसगढ़ में संस्कृत के साथ-साथ गोंडी जैसी क्षेत्रीय भाषा भी पढ़ाई जाती है। परेशानी उन अभिभावकों को होती है, जो एक शहर से दूसरे शहर में जाते हैं और उन्हें अपनी मन-पसंद की विदेशी भाषा पढ़ाने वाला स्कूल नहीं मिलता।

मोटे तौर पर बहुसंख्यक गैर-हिंदी राज्यों में बच्चे अंग्रेजी और हिंदी के साथ तीसरी भाषा के रूप में अपनी मातृभाषा सीखते हैं। राज्यों के बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के पाठ्यक्रमों में टकराव होता है। यह दिक्कत केवल हिंदी क्षेत्रों में ही नहीं है। दक्षिण में भी है, जहां बच्चों को तीसरी भाषा के रूप में तमिल, कन्नड़, मलयालम या तेलुगु पढ़नी पड़ती है। इससे उन्हें दिक्कत होती है, जो कक्षा पांच से जिस तीसरी भाषा को पढ़ रहे होते हैं, उसे छोड़ना पड़ता है। यों पांचवीं कक्षा तक भाषा का मूल्यांकन भी नहीं होता। कुछ लोगों को लगता है कि संस्कृत या उर्दू पढ़ने से उनके बच्चों का करिअर अच्छा नहीं होगा, विदेशी भाषा पढ़ने से होगा।

भाषा संबंधी प्राथमिकताएं भी राज्यों के अनुसार भिन्न होती हैं। मध्य प्रदेश में अब तक केवल दो-भाषा प्रणाली ही लागू है, जिसका पालन राज्य बोर्ड और सीबीएसई दोनों स्कूलों द्वारा किया जाता है। अभिभावक इंतजार कर रहे हैं कि क्या इस साल कोई बदलाव होगा। देश के बाहर सीबीएसई स्कूलों के साथ भी ऐसा ही है। तीसरी भाषा के रूप में विदेशी भाषा का चयन किया जा सकता है, पर सभी स्कूलों में सभी भाषाएं उपलब्ध नहीं होतीं।

कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि भाषाओं का बोझ गरीब तबके के बच्चों को पढ़ाई से विमुख करता है। उच्च-मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे को मिलने वाले विशेषाधिकार सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों से बिलकुल अलग होते हैं। पोषण संबंधी अंतर ही चौंकाने वाला है। और यह असमानता केवल शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में ही नहीं, बल्कि आदिवासी क्षेत्रों में भी स्पष्ट है।

मिड डे मील के कारण बच्चों को स्कूल आने की प्रेरणा मिलती है, लेकिन विषयों का बोझ उन्हें हतोत्साहित करता है। उनके अभिभावक अपने बच्चों के लिए ट्यूशन भी नहीं लगा सकते। पर भाषा के सवाल अलग-अलग उम्र के बच्चों के लिए अलग होते हैं। पांच-छह साल के बच्चे और बारह-चौदह साल के बच्चे की सीखने की प्रवृत्ति अलग होती है। इसलिए यह शिक्षा-मनोविज्ञान से जुड़ा विषय भी है।

सवाल है कि जो बच्चे पहले से फ्रेंच, जर्मन और स्पेनिश भाषा पढ़ रहे हैं, वे एक नई भारतीय भाषा को बिल्कुल नए सिरे से किस तरह से सीखेंगे? पर उन्हें विदेशी भाषा पढ़ने की हड़बड़ी क्यों है? वह तो पढ़ाई पूरी होने के बाद भी सीखी जा सकती है। उन्हें पढ़ाने वाले अध्यापकों को अपनी नौकरी जाने का डर है, वहीं बहुत से स्कूलों में इन भाषाओं को पढ़ने के इच्छुक छात्र हैं, पर अध्यापक नहीं हैं। ये समस्याएं शिक्षा की सामान्य समस्याओं से अलग नहीं हैं। अदालत के सामने इसके तमाम पक्ष खुलकर सामने आएंगे।

जम्बो ड्रग्स और युवाओं का बुझता भविष्य : जीरो टॉलरेंस की नीति बने

डॉ. सुधीर कुमार

आज का युवा जब हाथ में लेटेस्ट स्मार्टफोन लेकर 5 जी की रफ़्तार से दुनिया फतह करने का सपना देखता है, उसी समय उसकी दूसरी हथेली में जम्बो का एक छोटा सा पुड़ियानुमा पैकेट उसके अस्तित्व को शून्य करने की साजिश रच रहा होता है। यह सिर्फ एक नशा नहीं, यह भारत के भविष्य का केमिकल लोचा है। 21वीं सदी के भारत की चमक-धमक, स्टार्टअप्स और वैश्विक नेतृत्व के दावों के पीछे एक गहरा काला साया हमारी डेमोग्राफिक डिविडेंड यानी युवा शक्ति को निगल रहा है। दिल्ली के आलीशान पबों से लेकर पंजाब, हरियाणा और मुंबई की गलियों तक फैला यह जम्बो महज एक नशा नहीं, बल्कि घातक रसायनों का ऐसा कॉकटेल है जिसे ह्यमौत का सीधा आमंत्रण कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा।

जम्बो' वास्तव में कोई एक दवा नहीं, बल्कि मेफेड्रोन, हेरोइन और जानवरों को दिए जाने वाले ट्रांक्विलाइजर जैसे जाइलाजीन जैसे घातक रसायनों का एक अनियंत्रित कॉकटेल है। तस्कर इसकी अत्यधिक तीव्रता के कारण इसे जम्बो कहते हैं, जिसकी एक सूक्ष्म खुराक भी व्यक्ति को हफ़्तों तक मदहोश रख सकती है। वैज्ञानिक दृष्टि से यह मिश्रण मस्तिष्क के डोपामाइन सिस्टम को पूरी तरह नष्ट करने के साथ-साथ सीधे श्वसन और हृदय तंत्र पर प्रहार करता है, जो इसे सामान्य नशों की तुलना में कहीं अधिक जानलेवा बनाता है।

भारत में नशीली दवाओं के प्रसार को रोकने के लिए स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (एन-डी-पी-एस) सबसे सशक्त कानूनी हथियार है। इसकी धारा 8 मादक पदार्थों के व्यापार पर पूर्ण प्रतिबंध लगाती है, जबकि धारा 15 से 25 के तहत व्यावसायिक मात्रा में ड्रग्स पाए जाने पर 20 साल तक के कठोर कारावास का प्रावधान है। हालाँकि, जम्बो जैसे आधुनिक डिजाइनर ड्रग्स कानून के लिए चुनौती बने हुए हैं। इनके निर्माता नशीले पर्दाथों की आणविक संरचना में सूक्ष्म बदलाव कर देते हैं, जिससे ये प्रतिबंधित सूची से बाहर रह जाते हैं। यह कानूनी पेचीदगी स्पष्ट करती है कि ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई में कानून को निरंतर अपडेट करने और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है।

न्यायपालिका ने ड्रग तस्करी को समाज के विरुद्ध एक संगठित अपराध मानते हुए सख्त रुख अपनाया है। स्टेट ऑफ पंजाब बनाम बलदेव सिंह (1999) के ऐतिहासिक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि नशीले पदार्थों का अवैध व्यापार न केवल अर्थव्यवस्था को खोखला कर रहा है, बल्कि हमारी युवा पीढ़ी के स्वास्थ्य के लिए भी गंभीर खतरा है। इसी कड़ी में, हाल के वर्षों में अदालतों ने जमानत याचिकाएं खारिज कर पुनः यह स्पष्ट संदेश दिया है कि नशे के सौदागर के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए।

आज के दौर में रेव पार्टियां नशे को एक स्टेटस सिंबल और कूल दिखने के माध्यम के रूप में परोस रही हैं। सोशल मीडिया और वेब सीरीज के मायाजाल से भ्रमित होकर युवा इसे महज एक रोमांचक प्रयोग समझते हैं, जबकि यह प्रयोग वास्तव में उनके जीवन की अंतिम यात्रा का टिकट साबित हो सकता है। पर्दे पर नशे का महिमामंडन स्वतंत्रता लग सकता है, लेकिन हकीकत की जमीन पर यह केवल हंसते-खेलते परिवारों की बर्बादी की पटकथा लिखता है। युवाओं को यह समझना होगा कि दिखावे के स्वैगर और जीवन के संघर्ष के बीच एक बहुत बारीक रेखा है; क्योंकि अस्पताल के बिस्तर या जेल की सलाखों के पीछे कोई एटीट्यूड काम नहीं आता, वहां सिर्फ पछतावा शेष रह जाता है।

नशा केवल एक व्यक्तिगत पसंद नहीं, बल्कि एक पारिवारिक और सामाजिक त्रासदी है। एक व्यक्ति का नशा उसके माता-पिता के सपनों, अपनों के भरोसे और स्वयं के सुनहरे भविष्य को जड़ से खत्म कर देता है।

नशा मुक्ति के लिए कानून, तकनीक और संवेदना का समन्वय आवश्यक है। कानूनी स्तर पर, एन-डी-पी-एस मामलों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट और साइबर-निगरानी को कड़ा करना होगा, वहीं दूसरी ओर, सामाजिक स्तर पर, शिक्षा के माध्यम से जमीनी जागरूकता फैलानी होगी। दृष्टिकोण में बदलाव लाते हुए नशा करने वालों को अपराधी के बजाय उपचार योग्य रोगी के रूप में देखा जाना चाहिए। आधुनिक पुनर्वास केंद्रों के माध्यम से उन्हें सुधार कर समाज की मुख्यधारा में सम्मानजनक तरीके से पुनर्स्थापित करना हमारा लक्ष्य होना चाहिए।

आज नशा डिजिटल ट्रैपिंग के जरिए युवाओं के घर तक पहुंच चुका है, जहां डार्क वेब और एन्क्रिप्टेड ऐप्स ने इसे बेहद सुलभ बना दिया है। निस्संदेह, नशा अक्सर मानसिक तनाव या अकेलेपन का एक भ्रामक समाधान होता है। असली बहादुरी रसायनों के पीछे छिपने में नहीं, बल्कि जीवन की चुनौतियों का बिना किसी कृत्रिम सहारे के सामना करने में है। जम्बो जैसे जानलेवा पदार्थों से लड़ने के लिए केवल कानून पर्याप्त नहीं हैं; इसके लिए समाज और परिवारों में जीरो टॉलरेंस की नीति अनिवार्य है।

विंस्टन चर्चिल ने ठीक ही कहा था, जीत अंतिम नहीं है, हार घातक नहीं है; जारी रखने का साहस ही मायने रखता है। समय आ गया है कि हम अपनी तकनीक और प्रगति का उपयोग जहर फैलाने के लिए नहीं, बल्कि एक स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण के लिए करें। हमारी आज की जागरूकता ही कल की पीढ़ियों की सुरक्षा की गारंटी है। भारत का भविष्य स्माटफीन की धुंधली स्क्रीन पर नहीं, बल्कि उसके युवाओं के फौलादी स्वास्थ्य और सुदृढ़ चरित्र में सुरक्षित है।

लेखक कुरुक्षेत्र वि.वि के विधि विभाग में सहायक प्रोफेसर हैं।

सियासत में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी

डा. कर्म सिंह टाकुर

हिमाचल प्रदेश की महिलाएं केवल राजनीति तक सीमित नहीं हैं। वे प्रशासनिक सेवाओं, पुलिस विभाग, शिक्षा, चिकित्सा, परिवहन तथा तकनीकी क्षेत्रों में भी उल्लेखनीय कार्य कर रही हैंङ्घ हिमाचल प्रदेश सदैव सामाजिक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और जनकल्याण के क्षेत्र में अग्रणी राज्यों में गिना जाता रहा है। इसी क्रम में महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में भी प्रदेश ने देश के सामने एक प्रेरणादायक उदाहरण प्रस्तुत किया है। आज हिमाचल प्रदेश की महिलाएं केवल घर-परिवार तक सीमित नहीं हैं, बल्कि राजनीति, प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, सेना, न्यायपालिका और सामाजिक नेतृत्व जैसे अनेक क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा और क्षमता का लोहा मनवा रही हैं। विशेष रूप से पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी ने प्रदेश के लोकतंत्र को अधिक समावेशी और मजबूत बनाया है। हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2008 से पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण लागू करके पूरे देश में एक नई मिसाल कायम की थी। यह निर्णय केवल राजनीतिक प्रतिनिधित्व तक सीमित नहीं था, बल्कि महिलाओं को निर्णय प्रक्रिया का अभिन्न अंग बनाने की दिशा में एक क्रांतिकारी पहल थी। एक समय ऐसा था जब समाज में महिलाओं की भूमिका को केवल चूल्हा-चौका तक सीमित समझा जाता था।

महिलाओं को घर की चारदीवारी में ही रहने योग्य माना जाता था और यह धारणा प्रचलित थी कि वे पुरुषों के समान जिम्मेदारियां नहीं निभा सकतीं। किंतु बदलते समय, शिक्षा के प्रसार और सामाजिक जागरूकता ने इस सोच को पूरी तरह बदल दिया। आज हिमाचल की महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी दक्षता, मेहनत और नेतृत्व क्षमता का परिचय दे रही हैं। प्रदेश में होने वाले पंचायती राज चुनावों में महिलाओं की भागीदारी इस परिवर्तन का सबसे बड़ा उदाहरण है। हिमाचल प्रदेश की 3754 पंचायतों में 26, 28 और 30 मई को तीन चरणों में मतदान आयोजित किया जा रहा है। पंचायती राज संस्थाओं में कुल 31214 पदों पर चुनाव होने हैं, जिनमें से 15656 पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। यह आंकड़ा अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि प्रदेश सरकार महिलाओं को राजनीतिक नेतृत्व में समान अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इन चुनावों में लगभग 1900 पंचायतों की प्रधानी महिलाओं के हाथों में होगी। पंचायत सदस्य पदों के लिए 12709 महिलाएं चुनी जाएंगी, जबकि पंचायत समिति सदस्य के लिए 919 तथा जिला परिषद सदस्य के लिए 128 महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिलेगा। पंचायत प्रधानों के कुल 3758 पदों में से 453 पद अनुसूचित जाति वर्ग के लिए, 508 पद अनुसूचित जाति महिलाओं के लिए, 138 पद अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए तथा 151 पद अनुसूचित जनजाति महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 116 तथा ओबीसी महिलाओं के लिए 146 पद निर्धारित किए गए हैं। हर वर्ग की महिलाओं की राजनीति में भागीदारी से समाज में समरसता और समानता को बढ़ावा मिलता है। यह केवल आंकड़ों का विषय नहीं है, बल्कि यह सामाजिक परिवर्तन की कहानी है। महिलाओं को नेतृत्व का अवसर देकर हिमाचल प्रदेश ने यह सिद्ध किया है कि लोकतंत्र तभी मजबूत हो सकता है जब समाज के प्रत्येक वर्ग को समान प्रतिनिधित्व प्राप्त हो। जिस प्रदेश में महिलाओं की जनसंख्या पुरुषों के लगभग बराबर हो, वहां महिलाओं को नेतृत्व करने का समान अधिकार मिलना अत्यंत आवश्यक है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश की कुल जनसंख्या 6864602 है, जिसमें पुरुषों की संख्या 3481873 तथा महिलाओं की संख्या 3382729 है।

यह आंकड़ा स्पष्ट करता है कि प्रदेश की सामाजिक संरचना में महिलाओं की भागीदारी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए शासन और प्रशासन में उनकी भूमिका सुनिश्चित करना समय की मांग भी है और लोकतांत्रिक आवश्यकता भी। आज हिमाचल प्रदेश की महिलाएं केवल राजनीति तक सीमित नहीं हैं। वे प्रशासनिक सेवाओं, पुलिस विभाग, शिक्षा, चिकित्सा, परिवहन तथा तकनीकी क्षेत्रों में भी उल्लेखनीय कार्य कर रही हैं। प्रदेश की बेटियां भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, न्यायपालिका, सेना तथा अन्य प्रतिष्ठित सेवाओं में अपनी उत्कृष्ट पहचान बना रही हैं। यही कारण है कि आज समाज में महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण में व्यापक परिवर्तन देखने को मिल रहा है। कुछ दशक पहले तक यह कल्पना करना भी कठिन था कि महिलाएं बस चालक, टैक्सी चालक, कलेक्टर, पुलिस अधिकारी या चुनाव अधिकारी के रूप में कार्य करेंगी। लेकिन आज हिमाचल प्रदेश में महिलाएं सरकारी बसों का संचालन कर रही हैं, प्रशासनिक पदों पर कार्यरत हैं, चुनाव प्रक्रिया का संचालन कर रही हैं तथा अनेक ऐसे क्षेत्रों में सफलतापूर्वक कार्य कर रही हैं जिन्हें कभी ह्यपुरुष प्रधानह्न माना जाता था। लोकसभा और विधानसभा चुनावों में भी महिलाओं की भूमिका लगातार बढ़ रही है। पहले मतदान प्रक्रिया की जिम्मेदारी मुख्यतः पुरुष अधिकारियों और कमर्चारियों के हाथों में होती थी, लेकिन आज महिला मतदान अधिकारी, प्रेक्षक, पुलिस कर्मी तथा प्रशासनिक अधिकारी चुनावी प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी हैं। महिलाएं न केवल चुनावी प्रक्रिया को कुशलता से संचालित कर रही हैं, बल्कि अपनी ईमानदारी, संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के कारण प्रशासनिक कार्यों में नई पहचान भी स्थापित कर रही हैं।

हाल ही में नगर निगम मंडी चुनावों के दौरान महिला अधिकारियों और कमर्चारियों के माध्यम से चुनावी प्रक्रिया को देखने और समझने का अवसर प्राप्त हुआ। इस चुनाव प्रक्रिया में सहायक रिटर्निंग अधिकारी के रूप में कार्य कर रहीं रुपिंदर कौर, जो एक महिला आईएएस अधिकारी हैं, ने अत्यंत कुशलता और नेतृत्व क्षमता का परिचय दिया। उन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर पूरी चुनावी प्रक्रिया को सफलतापूर्वक संपन्न करवाया। विशेष बात यह रही कि उनके साथ कार्य करने वाली अधिकांश कमर्चारी महिलाएं थीं, जिन्होंने समर्पण, अनुशासन और जिम्मेदारी के साथ अपने दायित्व निभाए। चुनावों के दौरान अनेक नई चुनौतियां सामने आती हैं। कानून व्यवस्था बनाए रखना, मतदान केंद्रों की व्यवस्था, मतदाताओं की सहायता, तकनीकी समस्याओं का समाधान तथा निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करना अत्यंत कठिन कार्य होते हैं। किंतु आज महिलाएं इन सभी चुनौतियों का डटकर सामना कर रही हैं।

स्कूली शिक्षा गंभीर संकट का सामना कर रही

शिक्षा का प्रसार करने में भारत सफल है, मगर स्कूल से यूनिवर्सिटी तक लर्निंग क्वालिटी, तर्क-बुद्धि, शिक्षक क्षमता और रोजगार लायक योग्यता प्रदान करने के मामले में वह गहरे संकट का सामना कर रहा है।

गुणवत्ता संपन्न ज्ञान एवं तर्क क्षमता प्रदान करने के मामले में भारत की स्कूली शिक्षा गंभीर संकट का सामना कर रही है। नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट-'भारत में स्कूल शिक्षा प्रणाली: सामयिक विश्लेषण एवं गुणवत्ता वृद्धि के लिए नीतिगत मार्गइ- में यह बात स्वीकार की है। आयोग ने ये विस्तृत रिपोर्ट यूडीआईएसई+, एनएएस, प्रदर्शन आकलन समीक्षा, परख और असर रिपोर्टों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर तैयार की है। एक वाक्य में इसका सार है- 'शिक्षा का प्रसार करने में भारत ने सफलता हासिल की है, मगर लर्निंग क्वालिटी, शिक्षक क्षमता, और रोजगार पाने लायक योग्यताइ प्रदान करने जैसे मामलों में वह गहरे संकट का सामना कर रहा है।

प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक यही सूरत मौजूद है। स्पष्टतः शिक्षा के प्रसार से मतलब स्कूलों में दाखिले से है। आज देश में 14.7 लाख स्कूल, तकरीबन 24.7 करोड़ बच्चे और एक करोड़ शिक्षक हैं। मगर बुनियादी ज्ञान प्राप्त एवं प्रदान करने के मोर्चे पर स्थिति नाजुक है। ऊंचे क्लास में पहुंच जाने के बावजूद ज्यादातर छात्र निचले वर्ग का पाठ पढ़ने या अंकगणित के प्रश्नों को हल करने में नाकाम बने रहते हैं। क्लास बढ़ने के साथ समस्या बढ़ती चली जाती है। कई राज्यों के विश्वविद्यालयों की गुणवत्ता कमजोर है, शिक्षा का स्तर अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्ध्या के योग्य नहीं है, शिक्षा संस्थान फंडिंग और संचालन संबंधी समस्याओं से ग्रस्त हैं और इन सबका नतीजा है कि डिग्री लेकर निकले छात्रों को बाजार रोजगार के योग्य नहीं मानता।

आयोग ने कहा है कि बिखराव- ग्रस्त स्कूल प्रणाली, शिक्षकों की कमी, और असमान लर्निंग की स्थिति जैसे मसलों को हल नहीं किया गया, तो प्रगति का मार्ग प्रशस्त नहीं हो सकेगा। रिपोर्ट में शिक्षा व्यवस्था में आमूल सुधार की जरूरत बताई गई है। आधुनिक दौर के मुताबिक इन्फ्रास्ट्रक्चर निर्मित करने का सुझाव दिया गया है। मगर ये होगा कैसे? बजट पर गौर करें, तो साफ है शिक्षा सरकारों की प्राथमिकता नहीं है। ऊपर से ज्ञान एवं तर्क विरोधी माहौल राजनीतिक परियोजना के तहत बनाया जा रहा है। ऐसे में छात्र सीखने एवं तर्क करने की दिशा में कैसे प्रेरित होंगे?

नवा रायपुर में 20 हजार से अधिक पीपल के पेड़ लगाने का लक्ष्य, बनेगी पीपल सिटी

प्रकृति का संरक्षण हमारी संस्कृति का मूल मंत्र, पर्यावरण संरक्षण को जनआंदोलन बनाने की जरूरत – मंत्री चौधरी

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा राजधानी रायपुर में आयोजित संगोष्ठी एवं पुरस्कार वितरण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में वित्त, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी शामिल हुए। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की सचिव श्रीमती आर. संगीता विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा विकसित सीजी निगरानी पोर्टल, जैव–चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन विषयक फिल्म, मंडल की 25 वर्षों की उपलब्धियों पर आधारित लघु फिल्म, मंडल की नवीन वेबसाइट तथा ईको क्लब गतिविधियों पर आधारित स्मारिका का लोकार्पण किया गया।

भारतीय संस्कृति प्रकृति के संरक्षण और सह–अस्तित्व पर आधारित

मंत्री चौधरी ने पर्यावरण संरक्षण को जनआंदोलन बनाने का आह्वान करते हुए कहा कि पर्यावरण की रक्षा प्रत्येक नागरिक की साझा जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि आज पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन, बढ़ते तापमान, अनियमित वर्षा और पर्यावरणीय असंतुलन जैसी चुनौतियों का सामना कर रही है। इन समस्याओं का मूल कारण प्रकृति के साथ असंतुलित विकास मॉडल है। भारतीय संस्कृति सदैव प्रकृति के संरक्षण और उसके साथ सह–अस्तित्व की भावना पर आधारित रही है। यहां नदियों, पवर्तों, वृक्षों और जीव–जंतुओं तक को पूजनीय माना गया है। हमारी परंपरा प्रकृति के उपयोग की बात करती है, शोषण की नहीं।

मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि भारत हजारों वर्षों तक विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्था रहा, लेकिन उस दौर में पर्यावरण संकट, जलवायु परिवर्तन और सतत विकास जैसे विषयों पर चर्चा की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि विकास का आधार प्रकृति के साथ संतुलन था। औद्योगिक क्रांति के बाद दुनिया ने जिस विकास मॉडल को अपनाया, वह प्रकृति के अत्यधिक दोहन पर आधारित रहा और आज उसके दुष्परिणाम पूरी मानवता भुगत रही है। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन अब भविष्य की नहीं, वतर्मान की चुनौती बन चुका है। असामान्य वर्षा, बढ़ती गर्मी, सूखा और बाढ़ जैसी घटनाएं इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। प्रकृति के साथ अन्याय का परिणाम अंततः मानव समाज को ही भुगतना पड़ता है।

पर्यावरण संरक्षण में तकनीक का उपयोग बढ़ाया

मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार ने पर्यावरणीय निगरानी और प्रदूषण नियंत्रण के लिए कई महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। औद्योगिक इकाइयों की चिमनियों से निकलने वाले उत्सर्जन की ऑनलाइन निगरानी के लिए आधुनिक प्रणाली विकसित की गई है, जिससे प्रदूषण स्तर बढ़ते ही विभाग को तत्काल जानकारी मिलती है और त्वरित कारर्वाई संभव हो पाती है। उन्होंने बताया कि फ्लाई ऐश के सुरक्षित परिवहन और निपटान के लिए जीपीएस आधारित ट्रैकिंग प्रणाली लागू की गई है। साथ ही यह सुनिश्चित किया गया है कि अन्य राज्यों का फ्लाई ऐश छत्तीसगढ़ में डंप न किया जाए। खतरनाक अपशिष्टों के प्रबंधन को लेकर भी राज्य सरकार ने सख्त और नैतिक निर्णय लिए हैं, ताकि पर्यावरण और जनस्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

श्री चौधरी ने वृक्षारोपण की वतर्मान पद्धतियों पर भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि केवल औपचारिकता के लिए पौधे लगाने के बजाय स्थानीय और पर्यावरण की दृष्टि से उपयोगी वृक्षों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। पीपल, नीम, आम और अन्य देशी वृक्ष पर्यावरण संरक्षण में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने बताया कि रायपुर कलेक्टर रहते हुए उन्होंने पीपल फॉर पीपल अभियान प्रारंभ किया था। अब नवा रायपुर में 20 हजार से अधिक पीपल के वृक्ष लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में नवा रायपुर को ह्यपीपल सिटीह्व के रूप में विकसित किया जाएगा, जहां किसी भी दिशा में देखने पर पीपल का वृक्ष दिखाई देगा।

बच्चों में विकसित करनी होगी पर्यावरणीय संवेदनशीलता

आवास एवं पर्यावरण मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण केवल बड़े अभियानों से नहीं, बल्कि छोटी–छोटी आदतों से शुरू होता है। अनावश्यक बिजली की बचत, प्लास्टिक के उपयोग में कमी, पौधों की सही देखभाल और स्थानीय प्रजातियों के पौधों का वृक्षारोपण जैसी आदतें समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला सकती हैं। उन्होंने शिक्षकों और ईको क्लब समन्वयकों से आग्रह किया कि वे बच्चों में पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता विकसित करें। आने वाली पीढ़ी की सोच बदलकर ही पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में स्थायी परिवर्तन लाया जा सकता है।

सस्टेनेबिलिटी में युवाओं के लिए अपार संभावनाएं

मंत्री श्री चौधरी ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि सर्कुलर इकोनॉमी, अपशिष्ट प्रबंधन, प्लास्टिक रिसाइक्लिंग, हरित प्रौद्योगिकी और सतत विकास आधारित स्टार्टअप भविष्य के सबसे बड़े अवसरों में शामिल हैं। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण केवल सामाजिक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि रोजगार, नवाचार और उद्यमिता का भी बड़ा क्षेत्र बनकर उभर रहा है। उन्होंने युवाओं से आग्रह किया कि वे अपने करियर और उद्यमों को सस्टेनेबिलिटी के सिद्धांतों से जोड़ें और पर्यावरणीय चुनौतियों को अवसर में बदलने का प्रयास करें।

कार्यक्रम के दौरान अतिथियों ने पर्यावरण संरक्षण विषयक प्रदर्शनी का अवलोकन किया तथा तुलसी पौधे को जल अर्पित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मिशन लाइफ की शपथ दिलाई गई तथा विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत नुक्कड़ नाटक किस्सा लकड़ी का ने पर्यावरण संरक्षण का प्रभावी संदेश दिया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में ईको क्लब समन्वयकों एवं मास्टर ट्रेनर्स को मिशन लाइफ, ठोस एवं प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन तथा पर्यावरणीय गतिविधियों के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया। कार्यक्रम के दौरान पोस्टर प्रतियोगिता एवं विभिन्न पर्यावरणीय गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों, विद्यालयों और ईको क्लबों को सम्मानित भी किया गया। समारोह में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के सदस्य सचिव राजु अगसिमनि, प्रदेशभर से आए शिक्षकों, ईको क्लब समन्वयकों, विद्यार्थियों, विभागीय अधिकारी कर्मचारी एवं पर्यावरण संरक्षण से जुड़े विभिन्न संस्थानों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

खास खबर

आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित होगा रायगढ़ प्रेस क्लब भवन– वित्त मंत्री ओपी चौधरी

नई दृष्टिबिंदु / रायगढ़

वित्तमंत्री ओपी चौधरी ने आज सुबह डिग्री कॉलेज रोड स्थित निर्माणाधीन प्रेस क्लब भवन का निरीक्षण कर निर्माण कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि भवन निर्माण में पत्रकारों की व्यावसायिक आवश्यकताओं, आधुनिक तकनीकी सुविधाओं तथा भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कार्य किया जाए।

निरीक्षण के दौरान वित्त मंत्री श्री चौधरी ने भवन के ड्राइंग–डिजाइन, लेआउट, सभाकक्ष, कमरों की संख्या तथा प्रस्तावित सुविधाओं की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने कहा कि प्रेस क्लब केवल एक भवन नहीं बल्कि संवाद, विचार–विमर्श और अभिव्यक्ति का महत्वपूर्ण मंच होता है। इसलिए भवन का निर्माण ऐसा होना चाहिए जो पत्रकारों को बेहतर कार्य वातावरण उपलब्ध कराने के साथ–साथ विभिन्न आयोजनों के लिए भी उपयोगी सिद्ध हो। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस, सेमिनार और अन्य कार्यक्रमों को ध्यान में रखते हुए भवन में साउंड प्रूफिंग, आधुनिक ऑडियो–वीडियो सुविधाएं, व्यवस्थित बैठक व्यवस्था तथा आवश्यक तकनीकी संसाधनों का समावेश किया जाए। साथ ही भवन की संरचना ऐसी हो जो लंबे समय तक टिकाऊ, सुविधाजनक और उपयोगी बनी रहे। वित्त मंत्री श्री चौधरी ने निर्माण एजेंसी को गुणवत्ता के साथ समयबद्ध तरीके से कार्य पूर्ण करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि रायगढ़ प्रेस क्लब भवन पत्रकारों के लिए एक बेहतर कार्यस्थल के रूप में विकसित होगा, जहां संवाद, विमर्श और जनसरोकारों से जुड़े विषयों पर प्रभावी गतिविधियां संचालित की जा सकेंगी।

उल्लेखनीय है कि वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने गत 2 मई को वार्ड क्रमांक 27 में प्रस्तावित अत्याधुनिक प्रेस क्लब भवन का भूमिपूजन एवं शिलान्यास किया था। भूमिपूजन के महज एक माह के भीतर निर्माण कार्य प्रारंभ हो जाना परियोजना के प्रति शासन की गंभीरता और प्रतिबद्धता को दर्शाता है। करीब 50 लाख रुपए की लागत से बनने वाले इस आधुनिक प्रेस क्लब भवन के लिए भूमि संबंधी प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद शासन से 20 लाख रुपए तथा विधायक निधि से 30 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। भूमिपूजन कार्यक्रम के दौरान मंत्री श्री चौधरी ने कहा था कि प्रेस क्लब भवन की मांग को लेकर पत्रकार साथियों द्वारा लगातार प्रयास, संवाद और सकारात्मक फॉलोअप किया गया, जिसके परिणामस्वरूप यह महत्वपूर्ण कार्य प्रारंभ हो सका है।

इस अवसर पर महापौर नगर निगम जीवर्धन चौहान, सभापति डिग्रीलाल साहू, कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी सहित स्थानीय पार्षद, जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक तथा विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

प्रभावी कार्यशैली और नई तकनीकों को अपनाकर समस्याओं का करें त्वरित समाधान – अरुण साव

उप मुख्यमंत्री ने निर्माण कार्यों और योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की

नई दृष्टिबिंदु / 00000

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कोण्डागांव जिला मुख्यालय में लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, नगरीय प्रशासन एवं विकास तथा खेल एवं युवा कल्याण विभाग के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने जिले के तीनों नगरीय निकायों कोंडागांव , केशकाल और फरसगांव में वर्षा ऋतु के पहले आवश्यक तैयारियां समय पर पूर्ण करने, नागरिकों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने तथा स्वच्छता व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के निर्देश दिए। साथ ही सड़क, पुल एवं पुलिया निर्माण कार्यों को गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय–सीमा में पूर्ण करने पर जोर दिया।

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने बैठक में कहा कि कोण्डागांव जिला विकास की असीम संभावनाओं से परिपूर्ण है। केशकाल घाट बायपास के निर्माण से क्षेत्र के विकास को नई गति मिलेगी, इसलिए भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए योजनाबद्ध तरीके से कार्य करें। उन्होंने अधिकारियों से समय के साथ प्रभावी कार्यशैली अपनाने, नई तकनीकों का उपयोग करने तथा समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। श्री साव ने कहा कि नक्सलवाद के कारण यह क्षेत्र लंबे समय तक विकास की प्रतीक्षा करता रहा है, लेकिन अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं। दूरस्थ और वनांचल क्षेत्रों तक विकास की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सभी अधिकारी पूरी ऊर्जा, क्षमता और प्रतिबद्धता के साथ कार्य करें। उन्होंने कहा कि शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना हम सभी की जिम्मेदारी है और इसके लिए टीम भावना के साथ कार्य करना आवश्यक है।

उप मुख्यमंत्री ने नगरीय प्रशासन विभाग की समीक्षा के दौरान सभी मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को वर्षा ऋतु से पूर्व नालियों की सफाई पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने पेयजल की गुणवत्ता की नियमित जांच सुनिश्चित करने तथा अधिकारियों को अनिवार्यतः प्रातः भ्रमण करने के निर्देश दिए। द्वारा नियमित मॉर्निंग विजिट करने पर भी बल दिया। साथ ही रेन वाटर हार्वेस्टिंग के कार्यों को मिशन मोड में पूर्ण करने तथा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का व्यापक प्रचार–प्रसार कर पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित करने को कहा। उन्होंने सभी नगरीय निकायों को स्वच्छ, सुंदर एवं सुविधायुक्त बनाने पर विशेष जोर दिया।

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की समीक्षा के दौरान उप मुख्यमंत्री ने जल जीवन मिशन के कार्यों में अपेक्षित प्रगति लाने के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। उन्होंने सभी निर्माण एवं पेयजल योजनाओं का नियमित फील्ड निरीक्षण करने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में निर्बाध और गुणवत्तापूर्ण पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा। लोक निर्माण विभाग की समीक्षा के दौरान उन्होंने निर्माणाधीन सड़कों, पुलों एवं भवनों के निर्माण कार्यों की प्रगति का आकलन करते हुए कार्यों में तेजी लाने तथा उन्हें निर्धारित समय–सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने खेल विभाग की समीक्षा के दौरान खेल गतिविधियों के समन्वित एवं प्रभावी आयोजन सुनिश्चित करने को कहा।

बैठक में जल प्रदाय परियोजनाओं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) निर्माण, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी), आकांक्षी शौचालय निर्माण, राजस्व वसूली, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं सहित विभिन्न विभागीय योजनाओं एवं कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। कोंडागांव की कलेक्टर श्रीमती नुपूर राशि पन्ना, पुलिस अधीक्षक पंकज चन्द्रा, जिला पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती रीता शोरी और चारों विभागों के विभागाध्यक्ष कार्यालयों के वरिष्ठ अधिकारियों सहित सभी जिला स्तरीय अधिकारी भी बैठक में मौजूद थे।

केशकाल घाट बायपास रुट का किया निरीक्षण

उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने रायपुर–जगदलपुर मार्ग पर बहुप्रतीक्षित केशकाल घाट फोरलेन बायपास रुट का निरीक्षण किया। उन्होंने विभागीय अधिकारियों और निर्माण एजेंसी के साथ बायपास के दोनों छोरों का निरीक्षण कर बायपास के काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। श्री साव ने अधिकारियों से कहा कि बस्तर और छत्तीसगढ़ के लिए यह बायपास अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका तेजी से निर्माण कर आवाजाही शुरू करना सरकार की प्राथमिकता में है।

11.38 किमी का है बायपास, 2 वृहद और 2 मध्यम पुल भी बनेंगे : लोक निर्माण विभाग द्वारा 308 करोड़ रुपए की लागत से 11 .38 किमी लंबे केशकाल घाट बायपास का निर्माण किया जा रहा है। इस बायपास में दो वृहद और दो मध्यम पुल भी बनाए जाएंगे। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कोंडागांव जिले के केशकाल शहर में केशकाल से सलना तक सड़क मजबूतीकरण कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण एजेंसी को समय–सीमा में गुणवत्ता के साथ काम पूरा करने के निर्देश दिए। श्री साव नजदीक के बेड़मा गांव में जल जीवन मिशन के अंतर्गत जल अर्पण कार्यक्रम में भी शामिल हुए। विधायक नीलकंठ टेकाम और कलेक्टर श्रीमती नुपुर राशि पन्ना भी कार्यक्रम में शामिल हुईं।

एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत गुजरात पुलिस का 20 दिवसीय भ्रमण का समापन

एसपी अंकिता शर्मा ने किया सम्मान

नई दृष्टिबिंदु / राजनांदगां

एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत गुजरात से आए 15 सदस्यीय पुलिस दल का 17 मई से 06 जून तक राजनांदगांव रेंज में भ्रमण संपन्न हुआ। शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सभागार में एसपी अंकिता शर्मा ने गुजरात पुलिस के दल को भेंट देकर सम्मानित किया।

वर्ष 2026 के लिए गुजरात पुलिस कमिर्यों के भ्रमण हेतु छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव रेंज को चुना गया है। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत गुजरात राज्य को छत्तीसगढ़ राज्य के साथ एक जोड़ी राज्य के रूप में तय किया गया है। इसके तहत दोनों राज्यों के पुलिसकर्मी एक–दूसरे के राज्यों की कार्यप्रणाली का अवलोकन कर संस्कृति का आदान–प्रदान करेंगे और पुलिस कार्रवाई को देखेंगे–सीखेंगे।

20 दिन के भ्रमण के दौरान गुजरात पुलिस दल ने थाना आजाक/महिला प्रकोष्ठ/आईयूसीएडब्ल्यू इकाई, नगर सेना कार्यालय, जिला जेल, यातायात शाखा, साइबर इकाई का अवलोकन किया। साथ ही पुरातत्व एवं सांस्कृतिक स्थलों, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर, खैरागढ़–छुईखदान–गण्डई, कबीरधाम, मोहला–मानपुर–अंबागढ़ चौकी जिले के कार्यों की जानकारी ली। दल ने जिले के पर्यटन, धार्मिक एवं शैक्षणिक स्थलों का भी भ्रमण किया।

समापन पर गुजरात पुलिस दल ने छत्तीसगढ़ पुलिस के सहयोग के लिए आभार जताया। दल के सदस्यों ने कहा कि यहां की लोककला–संस्कृति से परिचित होकर गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की पुलिस कार्यप्रणाली सहज, सरल एवं मानवीयता पूर्ण है।

एसपी अंकिता शर्मा ने कहा कि यह कार्यक्रम अनुभव और विशेषज्ञता साझा करने तथा राष्ट्रीय सुरक्षा, कानून व्यवस्था और सांस्कृतिक समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। इसी क्रम में राजनांदगांव रेंज से भी 15 सदस्यीय पुलिस दल गुजरात के विभिन्न शहरों–जिलों के भ्रमण के लिए भेजा गया है। इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौर, नगर पुलिस अधीक्षक मंजूलता बाज एवं रक्षित निरीक्षक लोकेश कसेर उपस्थित थे।

धमतरी का 'महा–परिवर्तन' : 60 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड खरीदी और 30 हजार मीट्रिक टन का नया 'लॉजिस्टिक्स हब'

अब नहीं भटकेगा किसान, ब्रॉडगेज रेल और आधुनिक गोदामों से बदलेगी धमतरी की तकदीर

नई दृष्टिबिंदु / धमतरी

छत्तीसगढ़ का कृषि प्रधान जिला धमतरी आज विकास और आत्मनिर्भरता के एक नए दौर में प्रवेश कर रहा है। कभी रबी फसलों के रिकॉर्ड उपार्जन के बाद भंडारण की कमी से जूझने वाला यह जिला, आज अपनी मजबूत इच्छाशक्ति और प्रशासनिक दूरदर्शिता के कारण प्रदेश के एक प्रमुख 'वेयरहाउसिंग एवं कृषि लॉजिस्टिक्स हब' के रूप में उभर रहा है। राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ और छत्तीसगढ़ राज्य भंडारण गृह निगम के संयुक्त प्रयासों से जिले में 30 हजार मीट्रिक टन की अतिरिक्त वैज्ञानिक भंडारण क्षमता विकसित की जा रही है, जो धमतरी की ग्रामीण अर्थव्यवस्था और कृषि परिदृश्य को पूरी तरह बदलने के लिए तैयार है।

अतीत की चुनौती से लिया सबक

विगत वर्षों में धमतरी ने रबी फसलों, विशेषकर चने के रिकॉर्ड उत्पादन और उपार्जन का गवाह बना। लेकिन इस खुशी के साथ एक बड़ी चुनौती भी सामने आई।जिले में पर्याप्त भंडारण क्षमता का न होना। मजबूरी में उपज को दूसरे जिलों के गोदामों में भेजना पड़ा, जिससे न केवल परिवहन का खर्च बढ़ा, बल्कि प्रशासनिक और सहकारी संस्थाओं पर भी भारी दबाव पड़ा। इसी चुनौती को अवसर में बदलते हुए धमतरी प्रशासन ने जिले में ही स्थायी और आधुनिक भंडारण अधोसंरचना विकसित करने की एक व्यापक काययीजना पर काम शुरू किया।

'विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना' का मिला संबल

केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना धमतरी के लिए वरदान साबित हो रही है। इसके तहत जिले की चार प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों (पैक्स) का चयन किया गया है। जिसमे अंवरी, कोसमर्रा, पोटियाडीह–आमदी और कोलियारी शामिल है। इन चारों समितियों में 2,500–2,500 मीट्रिक टन क्षमता के आधुनिक गोदामों का निर्माण युद्ध स्तर पर जारी है। इनके पूरा होते ही ग्रामीण स्तर पर ही 10 हजार मीट्रिक टन की अतिरिक्त भंडारण सुविधा उपलब्ध हो जाएगी, जिससे स्थानीय किसानों को अपनी उपज सुरक्षित रखने के लिए दूर नहीं भटकना पड़ेगा। इसके साथ ही, राज्य भंडारण गृह निगम द्वारा धमतरी और कुरूद में 10–10 हजार मीट्रिक टन क्षमता के दो बड़े गोदाम विकसित किए जा रहे हैं। केंद्रीय भंडारण निगम (उहउ) के पास पहले से उपलब्ध 1 लाख मीट्रिक टन से अधिक की क्षमता के साथ अब धमतरी का नेटवर्क बेहद मजबूत होने जा रहा है।

रिकॉर्ड खरीदी और आर्थिक समृद्धि(रबी विपणन वर्ष 2026)

भंडारण क्षमता में यह विस्तार हवा में नहीं, बल्कि जमीन पर बढ़ती कृषि समृद्धि को देखकर किया जा रहा है। रबी विपणन वर्ष 2026 में जिले के 9,103 किसानों से 1 लाख 16 हजार 162 क्विंटल चने की रिकॉर्ड खरीदी की गई है, जिसके एवज में 60.54 करोड़ रुपये सीधे किसानों के खातों में भुगतान करने की प्रक्रिया जारी है। चने के साथ–साथ सरसों और मसूर का भी सफल उपार्जन किया गया है।

राइस मिलर्स और व्यापार को मिलेगी नई रफ्तार

धान मिलिंग के क्षेत्र में धमतरी हमेशा से अग्रणी रहा है, लेकिन अक्सर तैयार चावल और धान के सुरक्षित रख–रखाव की समस्या आती थी। इस नई क्षमता विस्तार से मिलिंग गतिविधियों में तेजी आएगी, भंडारण का दबाव कम होगा और परिवहन और लॉजिस्टिक्स की लागत में भारी कमी आएगी। इसके साथ ही, धमतरी में ब्रॉडगेज रेल लाइन पर जल्द शुरू होने वाला रैक संचालन जिले के विकास में चार चांद लगाने वाला है। रेल मार्ग जुड़ने से यहां का चावल और कृषि उत्पाद देश के बड़े बाजारों तक बेहद कम लागत में पहुंच सकेंगे।

धमतरी में विकसित हो रही वेयरहाउसिंग अधोसंरचना और जल्द प्रारंभ होने वाली ब्रॉडगेज रेल सेवाएं जिले को प्रदेश के प्रमुख लॉजिस्टिक्स एवं व्यापारिक केंद्र के रूप में स्थापित करेंगी। यह पहल रोजगार सृजन, व्यापार विस्तार और स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति देने में मील का पत्थर सिद्ध होगी। भंडारण क्षमता बढ़ने से कृषि उपज का बेहतर प्रबंधन, परिवहन लागत में कमी और विपणन व्यवस्था में सुधार होगा। यह नई अधोसंरचना किसानों, सहकारी संस्थाओं, व्यापारियों और उद्योगों के लिए दीघर्कालिक लाभ सुनिश्चित कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई मजबूती देगी।

धमतरी की यह सफलता की कहानी इस बात का जीवंत उदाहरण है कि कैसे सही समय पर सही बुनियादी ढांचे का निर्माण करके एक पूरे क्षेत्र की तकदीर बदली जा सकती है। आने वाले वर्षों में, भंडारण की यह सुदृढ़ व्यवस्था और रेल कनेक्टिविटी न केवल किसानों की आय में वृद्धि करेगी, बल्कि धमतरी को छत्तीसगढ़ के नक्शे पर एक बड़े 'कृषि–व्यापार और लॉजिस्टिक्स हब' के रूप में नई पहचान दिलाएगी।

तीसरी बार दूल्हा बनने जा रहे हैं आमिर खान! 5 जुलाई को गौरी स्प्रैट संग कर सकते हैं शादी

बॉलीवुड के 'मिस्टर परफेक्शनिस्ट' आमिर खान एक बार फिर अपनी निजी जिंदगी को लेकर चर्चा में हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, आमिर खान अपनी गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट के साथ तीसरी शादी करने जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि दोनों 5 जुलाई को विवाह बंधन में बंध सकते हैं। आमिर के करीबी सूत्रों के अनुसार, यह शादी बेहद सादगीपूर्ण तरीके से की जाएगी। दोनों परिवार के सदस्यों और कुछ करीबी दोस्तों की मौजूदगी में घर पर ही रजिस्टर्ड मैरिज करेंगे। रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि शादी के बाद फिल्म इंडस्ट्री के लिए किसी भव्य रिसेप्शन का आयोजन नहीं किया जाएगा। हालांकि, इस संबंध में अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। रिश्ते को सार्वजनिक करने के बाद से गौरी स्प्रैट कई मौकों पर आमिर खान के साथ नजर आ चुकी हैं। गौरी एक सात वर्षीय बेटे की मां हैं। बताया जाता है कि आमिर और गौरी लगभग 25 वर्षों से एक-दूसरे को जानते हैं और लंबे समय तक दोस्त रहने के बाद दोनों ने अपने रिश्ते को नया नाम देने का फैसला किया।

गौरतलब है कि मार्च 2025 में अपने 60वें जन्मदिन के अवसर पर आमिर खान ने मीडिया के सामने गौरी स्प्रैट को अपनी पार्टनर के रूप में परिचित कराया था। इस दौरान उन्होंने बताया था कि दोनों करीब 25 साल से दोस्त हैं, लेकिन कुछ समय पहले ही उनके बीच प्रेम संबंध की शुरुआत हुई। अगर आमिर और गौरी शादी करते हैं, तो यह अभिनेता की तीसरी शादी होगी। आमिर की पहली शादी रीना दत्ता से हुई थी, जिनसे उनके दो बच्चे जुनैद खान और ईरा खान हैं। वर्ष 2002 में दोनों का तलाक हो गया था। इसके बाद आमिर ने वर्ष 2005 में किरण राव से दूसरी शादी की। इस विवाह से उनका एक बेटा आजाद राव खान है। आमिर और किरण ने वर्ष 2021 में अलग होने का फैसला किया था। हालांकि, आमिर और गौरी की शादी को लेकर आधिकारिक पुष्टि का इंतजार किया जा रहा है।

डार्क किरदार पर बोलीं ईशा सिंह

कैमरे के पीछे ऑन और ऑफ होना आना चाहिए

टेलीविजन इंडस्ट्री की मशहूर अभिनेत्री ईशा सिंह आगामी फिल्म 'ऑब्सेस' की रिलीज को लेकर तैयार हैं। डार्क और सस्पेंस से भरपूर ट्रेलर रिलीज किया जा चुका है। साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म में डार्क किरदार को लेकर अभिनेत्री का कहना है कि एक एक्टर को पता होना चाहिए कि कब किरदार में रहना है और कब उससे बाहर निकलना है। अभिनेत्री ने बातचीत में बताया, 'एक एक्टर के तौर पर आपको यह अच्छी तरह पता होना चाहिए कि कैमरे के सामने कब किरदार में आना है (ऑन होना) और शॉट खत्म होने पर कब उससे बाहर निकलना है (ऑफ होना)। हां, यह सच है कि कुछ किरदार निभाते समय आप बहुत गहराई में चले जाते हैं लेकिन किस्मत से हमारी फिल्म के सेट का माहौल बहुत ही सकारात्मक और मददगार था। आसपास के लोग लगातार मेरा ख्याल रख रहे थे, जिसकी वजह से यह किरदार मुझ पर भावनात्मक रूप से भारी नहीं पड़ा।'

आज के समय में बढ़ते टॉक्सिक अटैचमेंट और जुनूनी व्यवहार पर बात करते हुए अभिनेत्री ने बताया कि सोशल मीडिया आने से पहले भी समाज में इस तरह के जुनूनी लोग मौजूद थे। उन्होंने कहा, 'फर्क बस इतना है कि अब सब कुछ बहुत जल्दी दिखाई देने लगता है क्योंकि हर किसी के पास फोन है और जानकारी तुरंत फैल जाती है। सोशल मीडिया के पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों पहलू हैं। 'ऑब्सेस' के बारे में मुझे जो बात सबसे ज्यादा पसंद आई, वह यह है कि इसकी कहानी में कई भावनात्मक परतें हैं। जब दर्शक यह फिल्म देखेंगे, तो वे समझ जाएंगे कि इन विषयों को कितनी गहराई से दिखाया गया है।'

अपनी बात को रखते हुए अभिनेत्री ने फिल्म के निर्देशक पीटर की बात को याद करते हुए कहा, 'पीटर सर ने एक बार कहा था, हर इंसान के अंदर एक फरिश्ता और एक शैतान, दोनों होते हैं। इनमें से कौन सा पहलू कितना बाहर आता है, यह पूरी तरह से उस इंसान पर निर्भर करता है।' अभिनेत्री ने किरदार के भावनात्मक बोझ से पूरी तरह मुक्त होने को जरूरी बताते हुए बताया कि काम के दौरान आप मानसिक रूप से उसी दुनिया में रहते हैं। कुछ दिन बहुत भारी होते हैं, तो कुछ अच्छे, लेकिन काम खत्म होते ही उस काल्पनिक दुनिया से बाहर निकलना एक कलाकार के मानसिक स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी है।

टाइगर श्रॉफ और विद्युत जामवाल साथ करेंगे फिल्म, मिलेगा एक्शन का डबल डोज

'बागी' फ्रैंचाइज की फिल्मों के जरिए टाइगर श्रॉफ ने दर्शकों के बीच अपने लिए एक खास जगह बनाई है। वहीं 'कमांडो' फेम एक्टर विद्युत जामवाल भी अपने जबरदस्त एक्शन के लिए फिल्मों में जाने जाते हैं। अब यह दोनों ही एक साथ फैंस को बड़े पर्दे पर नजर आ सकते हैं। जानिए, यह दोनों किस फिल्म प्रोजेक्ट का हिस्सा बन रहे हैं।

टाइगर श्रॉफ और विद्युत जामवाल ने एक पोस्ट इंस्टाग्राम पर फैंस के साथ शेयर की। इस पोस्ट में एआई इमेज से पोस्टर बनाया गया था, जिसमें दोनों एक्टर्स नजर आ रहे हैं। पोस्टर पर लिखा, 'दो लीजेंड, एक एपिक शोडाउन'। साथ ही टाइगर श्रॉफ वर्सेस विद्युत भी लिखा है। पोस्टर में दोनों एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। इस प्रोजेक्ट या फिल्म को टी-सीरीज पेश करेगा, इस बात का जिक्र भी पोस्टर पर किया गया है। इससे ज्यादा कोई जानकारी पोस्टर पर साझा नहीं की गई। फिल्म के नाम का भी जिक्र नहीं है।

टी-सीरीज के ऑफिस के बाहर दिखे थे टाइगर श्रॉफ और विद्युत

दोनों एक्टर्स के पोस्टर शेयर करने के बाद फैंस के बीच हलचल बढ़ गई। बता दें कि टाइगर श्रॉफ और विद्युत जामवाल को टी-सीरीज के ऑफिस के बाहर भी देखा गया था। ऐसा लगता है कि दोनों अपनी अपकमिंग फिल्म को लेकर चर्चा करने के लिए दोनों वहां पहुंचे थे।

टाइगर और विद्युत अपने करियर फ्रंटपर और क्या रहे हैं?

टाइगर श्रॉफ के करियर फ्रंट की बात करें तो पिछले साल वह फिल्म 'बागी 4' में दिखाई दिए थे। इस फिल्म को दर्शकों से अच्छा रेस्पॉन्स मिला था। वहीं विद्युत एक हॉलीवुड फिल्म 'स्ट्रीट फाइटर' में जल्द ही नजर आएंगे, इसमें भी वह जबरदस्त एक्शन करते हुए नजर आएंगे।

क्रिस्टन स्टीवर्ट के साथ बियारित्ज फिल्म फेस्टिवल की जूरी में शामिल होंगे ईशान खट्टर

अभिनेता ईशान खट्टर हॉलीवुड अभिनेत्री क्रिस्टन स्टीवर्ट और अन्य कई जाने-माने नामों के साथ बियारित्ज फिल्म फेस्टिवल के चौथे एडिशन में जूरी पैनल में शामिल होंगे। यह घोषणा खुद फिल्म फेस्टिवल की ओर से की गई है। ईशान के साथ-साथ फ्रांसीसी निर्देशक, स्क्रिप्ट राइटर और एडिटर नाथन एम्ब्रोसियोनी, फ्रांसीसी अभिनेत्री सूजी बेम्बा, कनाडाई अभिनेत्री व्हिटनी पीक और अन्य लोग भी शामिल होंगे।

पहली फिल्म से ही हुई ईशान के इंटरनेशनल करियर की शुरुआत

ईशान खट्टर के इंटरनेशनल करियर की शुरुआत उनकी पहली फिल्म 'बियॉन्ड द क्लाउड्स' से ही हो गई थी। इसे 2018 में ईरानी फिल्म निर्माता माजिद मजीदी ने निर्देशित किया था। इसके बाद उन्होंने 2021 में लियोनार्डो डि कैप्रियो और जेनिफर लॉरेंस स्टारर फिल्म 'डोंट लुक अप' में एक कैमियो भूमिका निभाई। 2020 में उन्होंने मीरा नायर की ब्रिटिश सीरीज 'ए सूटेबल बॉय' में तब्बू के साथ मुख्य भूमिका निभाई। उनकी 2025 में आई फिल्म 'होमबाउंड' को ऑस्कर के लिए भारत की आधिकारिक एंट्री के रूप में चुना गया था और इसे शॉर्टलिस्ट भी किया गया था।

इस फिल्म में नजर आएंगे ईशान खट्टर

वर्कफ्रंट की बात करें तो ईशान खट्टर आखिरी बार पिछले साल रिलीज हुई फिल्म 'होमबाउंड' में नजर आए थे। दो दोस्तों की कहानी और जातिवाद जैसे गंभीर मुद्दे पर बात करती इस फिल्म को ऑस्कर के लिए भी भारत की ओर से भेजा गया था। फिल्म को कान समेत कई फिल्म फेस्टिवल में भी काफी सराहा गया। नीरज घेवान द्वारा निर्देशित इस फिल्म में ईशान के साथ विशाल जेठवा और जान्हवी कपूर भी प्रमुख भूमिकाओं में नजर आए हैं। वहीं उनकी आगामी फिल्मों में पलाश वासवानी द्वारा निर्देशित फिल्म 'जुगाडू' शामिल है। इसके अलावा पिछले साल आया उनके शो 'द रॉयल्स' के भी दूसरे सीजन की तैयारी चल रही है।

सबसे अहम सीख फिल्म 'वीर-जारा' में काम करते हुए मिली

वेब सीरीज 'चिरैया' को लेकर चर्चा में आईं दिव्या दत्ता ने कहा- क्टरों के परिवार से होने के बावजूद हमेशा से पिक्चर साफ थी कि मुझे ऐक्टिंग इंडस्ट्री का रास्ता चुनना है। उन्होंने कहा- सबसे अहम सीख फिल्म वीर-जारा में शाहरुख खान के साथ काम करते हुए मिली।

कई कलाकार अपने किरदारों से पहचाने जाते हैं लेकिन दिव्या दत्ता उन चेहरों में से हैं, जो हर किरदार में खुद को थोड़ा-थोड़ा छोड़ती चली जाती हैं। लुधियाना की सादगी से लेकर सिनेमा की गहराइयों तक उनका सफर किसी शोर का नहीं बल्कि एक शांत भरोसे का रहा है, दिल की सुनने का भरोसा। उनके लिए अभिनय सिर्फ संवाद नहीं, खामोशियों को महसूस करने की कला है। फैसले हों या किरदार, वे आज भी उसी रास्ते पर चलती हैं, जहां दिमाग से पहले दिल जवाब देता है और शायद यही उन्हें अलग बनाता है। लखनऊ में शूट हुई वेब सीरीज 'चिरैया' के लिए शहर आईं दिव्या दत्ता से खास बातचीत।

दिल से बड़ा मेरा कोई साथी नहीं

लुधियाना में पली-बढ़ी दिव्या दत्ता कहती हैं कि मैंने अपने घर से बहुत कुछ सीखा है लेकिन कई बातें वक्त के साथ समझ में आती हैं। फिल्मों और शोज को चुनते समय मैं सिर्फ दिल की सुनती हूं। मुझे लगता है कि जो काम मैं दिल से करूंगी, वही मुझे आगे बढ़ने का मौका देगा। मेरे फैसले पहले भी दिल से होते थे और आज भी वही तरीका है क्योंकि दिल से बड़ा कोई साथी नहीं होता है। यही वजह है कि डॉक्टरों के परिवार से होने के बावजूद हमेशा से पिक्चर साफ थी कि मुझे ऐक्टिंग इंडस्ट्री का रास्ता चुनना है। मैं खुद को खुशकिस्मत भी मानती हूं कि मां ने मुझे अपनी पसंद चुनने की पूरी आजादी दी थी।

माहौल इंसानी और सम्मानजनक हो

मैंने कई अनुभवी कलाकारों के साथ काम करते हुए बहुत कुछ सीखा है। हालांकि, मुझे सबसे अहम सीख फिल्म वीर-जारा में शाहरुख खान के साथ काम करते हुए मिली। उस वक्त मुझे कैमरा एंगल्स का ज्यादा आइडिया नहीं था। उन्होंने खुद मुझे सही जगह पर खड़े होने में मदद की। वह इतने बड़े सुपरस्टार हैं, उन्हें क्या जरूरत थी मेरे लिए आगे आने की पर वो आए। उन्होंने यह भी कहा था कि मैं हर जगह मौजूद नहीं रहूंगा तो तुम्हें चीजें अपने हिसाब से बेहतर करनी होंगी। मुझे यह बात हमेशा याद रही। आज अगर मैं सीनियर हो गई हूं तो कोशिश करती हूं कि नए लोगों की जितनी मदद कर सकूं, करूं। सबसे जरूरी बात यही है कि सेट पर लोग एक-दूसरे के साथ कंफर्टेबल महसूस करें। काम तभी अच्छे से होता है, जब माहौल इंसानी और सम्मानजनक हो।

भीतर का शांत जागरण है

चिरैया किसी लाउड विद्रोह की कहानी नहीं है बल्कि भीतर होने वाले एक शांत जागरण की बात करती है। हर दृश्य का अपना स्वभाव होता है। कभी कुछ कहना जरूरी होता है और कभी बिल्कुल शांत रहना। सब कुछ सीन के पूरे ढांचे पर निर्भर करता है। जैसे सीन की मांग होती है, वैसा ही भाव अपनाया जाता है। कहीं शब्द जरूरी होते हैं, कहीं खामोशी ही सबसे बड़ा संवाद बन जाती है। मुझे लगता है कि सवाल से ज्यादा जरूरी है उसे कहने का तरीका।बात किस शांति से, किस प्यार से और किस सम्मान के साथ कही जाती है, यही फर्क पैदा करता है। 'शादी कोई लाइसेंस नहीं है' जैसे संवाद सवाल जरूर उठाते हैं, लेकिन किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं बल्कि सोचने के लिए मजबूर करने के इरादे से।

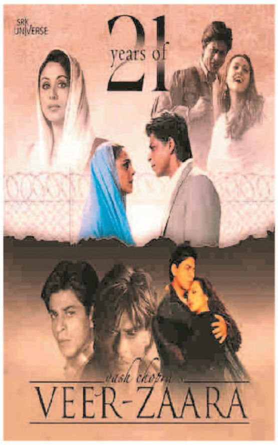

नगर पालिक निगम, भिलाई के
महापौर
नीरज पाल जी
को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं...
Happy Birthday
7 June
विनीत : समस्त कांग्रेस पार्षद नगर निगम, भिलाई

पीएससी मुख्य परीक्षा शुरू, कलेक्टर ने किया केंद्र का निरीक्षण

436 परीक्षार्थियों के लिए व्यवस्था, दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए अलग कक्ष

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग

छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित मुख्य परीक्षा शनिवार से शुरू हो गई। कलेक्टर अभिजीत सिंह ने परीक्षा शुरू होने से पहले सुबह 8:30 बजे शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज दुर्ग परीक्षा केंद्र पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया।

कलेक्टर ने केंद्राध्यक्ष को आयोग के निर्देशों के तहत बेहतर ढंग से परीक्षा संचालन के निर्देश दिए। साथ ही परीक्षार्थियों के लिए पेयजल, रोशनी, पंखे आदि आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करने को कहा।

परीक्षा केंद्र में कुल 436 परीक्षार्थियों के लिए व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं। कलेक्टर ने परीक्षा कक्षों, सुरक्षा व्यवस्था, पेयजल, शीतलन एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं का निरीक्षण कर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने विशेष रूप से दिव्यांग अभ्यर्थियों के प्रबंधों की जानकारी ली। केंद्र में तीन दिव्यांग प्रतिभागियों और उनके स्क्राइब के लिए अलग-अलग कक्षों में परीक्षा की व्यवस्था की गई है।

निरीक्षण के दौरान बताया गया कि प्रत्येक परीक्षा कक्ष में जैमर, कूलर एवं स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था है। कलेक्टर ने परीक्षा की गोपनीयता एवं निष्पक्षता बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। केंद्र अधीक्षक व संबंधित अधिकारियों को सतकर्ता एवं अनुशासन बनाए रखने को कहा गया। कलेक्टर ने परीक्षार्थियों से अपील की कि वे परीक्षा शुरू होने से कम से कम एक घंटा पहले केंद्र पहुंचें और आवश्यक दस्तावेज साथ लाएं।

इस अवसर पर परीक्षा केंद्र के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे। प्रशासन ने परीक्षा को शांतिपूर्ण, पारदर्शी एवं व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं।

चोरी का अनाज खरीदने वाले दो व्यापारी गिरफ्तार

नई दृष्टिबिंदु / राजनांदगांव

पुलिस ने ममता नगर औद्योगिक क्षेत्र स्थित अनाज गोदाम में हुई लाखों रुपये की चोरी के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए चोरी का अनाज खरीदने वाले दो व्यापारियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2 लाख 43 हजार रुपये से अधिक की नगदी और अनाज बरामद किया है। इससे पहले चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले दो मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मार्च 2026 में ममता नगर औद्योगिक क्षेत्र के एक अनाज गोदाम से चना खंडा, सोयाबीन और मसूर सहित करीब 4.50 लाख रुपये मूल्य का अनाज चोरी हो गया था। गोदाम संचालक की शिकायत पर सिटी कोतवाली थाना में अपराध क्रमांक 286/2026 दर्ज कर मामले की जांच शुरू की गई थी। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई और मुखबिरों से भी जानकारी जुटाई गई। जांच के दौरान पुलिस ने पहले मुख्य आरोपी राहुल कुर्रे और दिनेश साहू को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में दोनों आरोपियों ने चोरी की वारदात में अपनी संलिप्तता स्वीकार की थी। उनके कब्जे से चोरी के अनाज की बिक्री से प्राप्त 7,900 रुपये भी बरामद किए गए थे। बाद में दोनों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान देवेन्द्र साहू (35 वर्ष), निवासी ग्राम बरगाही और जयंत कुमार अग्रवाल (50 वर्ष), निवासी शांति नगर ढाबा रोड के रूप में हुई है। पुलिस ने दोनों के ठिकानों पर कार्रवाई कर चोरी के माल से जुड़े साक्ष्य जुटाए। पुलिस के अनुसार, आरोपियों के कब्जे से 29 किलोग्राम सोयाबीन, 5 किलोग्राम चना तथा 2 लाख 42 हजार 500 रुपये नगद बरामद किए गए हैं।

जब्त की गई सामग्री और नगदी की कुल कीमत 2 लाख 43 हजार 960 रुपये आंकी गई है। अधिकारियों का कहना है कि मामला केवल चोरी तक सीमित नहीं है। बल्कि चोरी के माल की खरीद-फरोख्त से जुड़े नेटवर्क की भी जांच की जा रही है।

स्वास्थ्य लाभ के बाद हैदराबाद से लौटे सभापति कृष्णा चंद्राकर

समाजसेवियों ने जाना उनका कुशलक्षेम

नई दृष्टिबिंदु / भिलाई

स्वास्थ्य लाभ के पश्चात हैदराबाद से लौटने पर भिलाई-चारोदा नगर निगम के सभापति कृष्णा चंद्राकर से सर्व समाज कल्याण समिति के पदाधिकारियों ने सौजन्य भेंट की। प्रतिनिधिमंडल ने उनका कुशलक्षेम जाना और उत्तम स्वास्थ्य एवं दीर्घायु जीवन की मंगलकामनाएं कीं।

इस अवसर पर सर्व समाज कल्याण समिति के अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह छोटू, महासचिव मलकीत सिंह, उपाध्यक्ष जोगा राव, सचिव शाहनवाज कुरैशी, वाजिद अंसारी, लक्की भल्ला सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे। सभापति कृष्णा चंद्राकर ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जनता के स्नेह और शुभकामनाओं से उन्हें शीघ्र स्वास्थ्य लाभ मिला है। उन्होंने क्षेत्र के विकास कार्यों को लेकर प्रतिबद्धता दोहराई।

राजनांदगांव पुलिस ने की कबाड़ी दुकानों की आकस्मिक जांच

चोरी का सामान नहीं मिला, कबाड़ियों को चोरी का माल न खरीदने की दी सख्त हिदायत

नई दृष्टिबिंदु / राजनांदगांव

थाना सिटी कोतवाली पुलिस ने शुक्रवार को शहर की कबाड़ी दुकानों में आकस्मिक चेकिंग अभियान चलाया। पुलिस अधीक्षक सुश्री अंकिता शर्मा के निर्देश पर हुई इस कार्रवाई में किसी भी दुकान से चोरी का सामान बरामद नहीं हुआ।

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौर व नगर पुलिस अधीक्षक अलेक्जेण्डर किरो के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी उपेन्द्र कुमार शाह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने रफीक कबाड़ी ममता नगर, मुन्ना कबाड़ी भरका पारा, गनी कबाड़ी पुराना गंज चौक, सलीम कबाड़ी खैरा रोड कन्हारपुरी और अरूण कबाड़ी लखोली नाका की दुकानों व गोदामों की जांच की।

जांच के दौरान कोई आपत्तिजनक या चोरी का सामान नहीं मिला। पुलिस ने सभी कबाड़ियों को लोहा समेत चोरी का कोई भी सामान न खरीदने की सख्त हिदायत दी। साथ ही समझाइश दी गई कि यदि कोई व्यक्ति चोरी का सामान बेचने दुकान में आता है तो उसकी सूचना तत्काल थाने में दें। कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक उपेन्द्र कुमार साहू, सउनि संजीव कुमार मालेकर, आरक्षक राजेश साहू, अश्वनी ठाकुर और पूरन वर्मा की सराहनीय भूमिका रही।

पीएम राहत योजना : कलेक्टर ने 9 प्रकरणों का किया भुगतान

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग

सड़क दुर्घटनाओं में घायलों को गोल्डन आवर में इलाज न मिलने से होने वाली मौतों को रोकने के लिए शुरू की गई पीएम राहत कैशलेस आपातकालीन उपचार योजना का लाभ जिले में मिलने लगा है। कलेक्टर अभिजीत सिंह ने आज अस्पतालों से प्राप्त 9 प्रकरणों का सफलतापूर्वक भुगतान किया।

पीएम राहत भारत सरकार की कैशलेस आपातकालीन उपचार योजना है जो समाज के सभी वर्गों के लिए है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी सड़क दुर्घटना में पीड़ित की मृत्यु केवल पैसों की कमी या समय पर इलाज न मिलने के कारण न हो।

इस योजना के तहत दुर्घटना के पहले 7 दिनों तक या 1.5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज सरकार के सहयोग से किसी भी पंजीकृत अस्पताल में कराया जा सकता है। अक्सर देखा गया है कि दुर्घटना पीड़ितों का सही समय पर इलाज न मिलने के कारण गोल्डन आवर में मृत्यु हो जाती है। यह योजना उसी को रोकने के लिए है। भुगतान के दौरान स्वास्थ्य विभाग से सीएमएचओ डॉ. मनोज दानी, डीएचओ डॉ. संजीव ग्लेड, अनूज कुमार रवि, आरटीओ से सनत बंजारे, लोकेश पाटिल तथा एनआईसी से विपिन देवांगन एवं अरूण सोनी उपस्थित थे।

सरगुजा : प्रेम संबंध में बाधा बन रही बुजुर्ग महिला की हत्या, प्रेमी-प्रेमिका गिरफ्तार

नई दृष्टिबिंदु / अंबिकापुर-लखनपुर

प्रेम संबंध में बाधा बन रही 65 वर्षीय महिला की हत्या के मामले में लखनपुर पुलिस ने प्रेमी-प्रेमिका को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है। सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी जांच से पूरे मामले का खुलासा हुआ। डीआईजी एवं एसएसपी राजेश कुमार अग्रवाल के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। थाना लखनपुर में रंजीत लकड़ा निवासी भुईंयापारा, जुना लखनपुर ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी 65 वर्षीय मां लक्ष्मी लकड़ा की 31 मई की रात 9 बजे से 1 जून की सुबह 7 बजे के बीच अज्ञात कारणों से मौत हो गई है।

पीएम रिपोर्ट में हत्या की पुष्टि : मर्ग कायम कर जांच में महिला विवेचक के साथ घटना स्थल का निरीक्षण किया गया। शव पर अलग-अलग जगह चोट और रगड़ के निशान मिले। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टर ने मृत्यु को हत्यात्मक बताया। इस पर थाना लखनपुर में अज्ञात के खिलाफ धारा 103(1) बीएनएस के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू की गई।

सीसीटीवी से पकड़ में आए आरोपी : जांच के दौरान घटनास्थल के पास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। फुटेज में रात में एक युवक मृतिका के घर अंदर जाते और कुछ देर बाद बाहर निकलते दिखा। इसके बाद मृतिका की भतीजी तेरेसा एक्का भी घर से निकलकर उसी युवक के साथ मोटर साइकिल से जाते दिखी। तकनीकी जानकारी के आधार पर पुलिस ने मृतिका की भतीजी 20 वर्षीय तेरेसा एक्का निवासी लोसगा, रानीकछार और उसके प्रेमी 30 वर्षीय आशिष कुमार गुप्ता निवासी बाजारपारा लखनपुर को हिरासत में लिया।

प्रेम संबंध छुपाने के लिए की हत्या : पूछताछ में दोनों ने बताया कि मृतिका लक्ष्मी लकड़ा उनके प्रेम संबंध में बाधा बन रही थी। इसी बात को लेकर और प्रेम संबंध छुपाने के लिए दोनों ने मिलकर लक्ष्मी को पकड़कर दीवार पर धक्का देकर मारपीट की और हत्या कर दी। वारदात के बाद दोनों रातभर बाहर रहे।

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल, कपड़े व अन्य सामान जब्त किया है। दोनों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। कार्रवाई में थाना प्रभारी उपनिरीक्षक संपत पोटाई, सउनि परशु राम, प्रधान आरक्षक सतीष सिंह, पिताम्बर सिंह, अजय पाण्डेय, प्रवीण चंद तिवारी, आरक्षक दशरथ राजवाडे की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

"यह समाचार पत्र आलोक तिवारी द्वारा 80/बी, मैत्री विहार, राधिका नगर, सुपेला, भिलाई, जिला दुर्ग, (छत्तीसगढ़)-490023 से आलोक तिवारी की ओर से प्रकाशित की जाती है, जिसका संपादन आलोक तिवारी द्वारा किया जाता है तथा इसका मुद्रण समय दर्शन प्रिंटर्स एंड पब्लिशर्स द्वारा प्लॉट नं. 339/6, गली नं. 02, पाटन, थाना उतई, दुर्ग, (छ.ग.)-491111 पर किया जाता है। (समाचार चयन के लिए PRP Act, 2023 के तहत संपादक जिम्मेदार है)। समस्त विवादों का निपटारा न्यायालयीन क्षेत्र दुर्ग होगा।" संपादक आलोक तिवारी, मो. 74154-69100